न्यू देहली पोस्ट

■ वर्ष 13 ■ अंक 12 रविवार (साप्ताहिक) 30 मार्च 2025 ■ पृष्ठ 16 ■ मूल्य 5 रुपये

‘कुली’ से श्रुति हासन का नया पोस्टर आउट

अंदर विशेष

मोदी सरकार के खिलाफ अदालत पहुंची एलन मस्क की कंपनी
पृष्ठ 3 पर

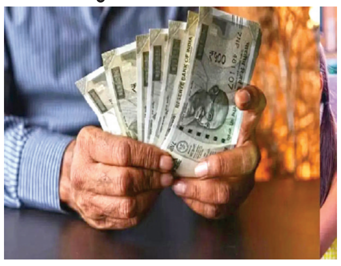

इंडस वैली रिपोर्ट : इंडिया के भीतर तीन इंडिया
पृष्ठ 5 पर

लोकपाल और हाईकोर्ट की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट का दखल
पृष्ठ 7 पर

बस्तर होगा 2026 तक नक्सल मुक्त!
पृष्ठ 9 पर

तेलंगाना : ओबीसी के लिए 42% आरक्षण का ऐलान
पृष्ठ 11 पर

भारत-चीन में बढ़ी बातचीत की सम्भावना
पृष्ठ 15 पर

राम मंदिर से भी बड़े आंदोलन की तैयारी

ब्राह्मणों के कब्जे से बौद्ध विहार मुक्त हो, एक हुए दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु

न्यू देहली पोस्ट डेस्क

क्या भारत में एक बार फिर होगा राम मंदिर से भी बड़ा आंदोलन. ?क्या ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त होगा बोधगया का बौद्ध विहार ? किसने दिया बोधगया को बुद्ध पूर्णिमा तक आजाद करने का अल्टीमेट ?

किसने कहा बौद्ध भूमि की आजादी होगी और किसने कहा तब मिलेगी हमारी असली आजादी ?

दुनिया भर के बौद्ध हुए एकजुट और कर दिया है महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन का ऐलान।

1947 में देश आजाद हुआ...अंग्रेजों के बनाए कानून बदल दिए गए। भारत अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। लेकिन बौद्धों के साथ क्या हुआ? एक कानून आया जिसे बोध गया टेंपल एक्ट-1949 कहा गया। इसी एक्ट के साथ और बौद्धों की पवित्र भूमि पर एक बोर्ड गठित कर दिया गया जिसे चार ब्राह्मण और जिला मजिस्ट्रेट मिलकर नियंत्रित करने लगे। इसी बोर्ड में चार भिक्षु भी शामिल किए गए। धर्म निरपेक्ष राज्य में बौद्धों से... उनकी ही पवित्र भूमि पर उनके अधिकार छीन लिए गए। ठीक उसी तरह जैसे अंग्रेजों ने भारत को नियंत्रित करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स और उसके पिट्ठुओं को सारी शक्ति दे दी थी जिसे कहा गया था. न्यू पालिसी ऑफ़ पारा माउन्टेसी। गया की पवित्र भूमि पर पीपल के वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।

आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जो बिहार के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल बोधगया में पिछले १२ फरवरी से जारी है। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बीटी एक्ट यानी बोधगया टेंपल एक्ट, 1949 ख़त्म किया जाए और महाबोधि मंदिर का पूरा नियंत्रण बौद्धों को सौंप दिया जाए।

शेष १ पर

विवादों का अड्डा बना ए आई ग्रोक, पीएम मोदी के झूठ का किया खुलासा

न्यूज़ डेस्क

ग्रोक ने प्रधानमंगतरी मोदी को झूठा ठहराया है। गोदी मीडिया के कई पत्रकारों को भी इसने नंगा किया है और उसके असली चरित्र का भी बखान किया है। लेकिन मोदी को झूठा बताने के बाद ग्रोक को लेकर बीजेपी कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई है। बीजेपी को लग रहा है कि अगर ग्रोक ऐसे ही खुलासा करता रहा तो बीजेपी की राजनीति प्रभावित हो सकती है। इस पर और भी चर्चा करेंगे और मोदी के बारे में ग्रोक ने क्या कुछ कहा है सामने रखेंगे लेकिन पहले ग्रोक के बारे में कुछ बातें जरुरी है। ग्रोक को व्यंग्य और ह्यूमर पसंद तो है ही वह सटीक और विश्लेषणात्मक जानकारी भी दे रहा है। कुछ ऐसी भी जानकारी ग्रोक दे रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सच तो यह है कि एलन मस्क का यह आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस अपने मालिक के बारे में भी सच कहने से नहीं चुकता। एक सवाल के जबाव में इसी ग्रोक ने अपने मालिक मस्क को सबसे बेकार आदमी बताया है ।

ग्रोक यूजर्स के सवालों के लहजे को समझकर उसी अंदाज में जवाब देता है। यही कारण है कि कभी-कभी यह गालियों में जवाब भी दे देता है। भारत में खासतौर पर राजनीतिक हलकों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है? इसके कई जबाव से बीजेपी परेशान हो गई है। बीजेपी का आईटी सेल जो हमेशा सामने वालों के बारे में झूठ फैलाता है अब इसकी सच्चाई भी ग्रोक सामने ला रहा है। वह बेबाकी से वह सब कुछ कहता है जो गोदी मीडिया कह नहीं पाती। गोदी मीडिया बी ही ग्रोक से परेशान हो गया है। ऐसे में जाने लगा है कि ग्रोक एआई तकनीक की नई क्रांति है या फिर विवादों का एक नया अड्डा? ग्रोक एआई , इलॉन मस्क की एआई कंपनी एक्स एआई द्वारा विकसित एक चैटबॉट है। इसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था और अब तक इसके तीन वर्जन आ चुके हैं।

शेष १ पर

विजयी मुस्कान के साथ अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम

न्यू देहली पोस्ट

नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स यूं तो पहले भी दो बार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जा चुकी हैं लेकिन शायद ही उन्होंने यह कल्पना की होगी कि तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने के बाद उन्हें वापसी के लिए लंबा इंतजार करना होगा और यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स नौ महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद भारतीय समय अनुसार बुधवार 19 मार्च को तड़के पृथ्वी पर लौट आए।

सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने दो अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेसएक्स यान पर सवार होकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अलविदा कहा। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स की यह तीसरी अंतरिक्ष उड़ान थी और उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए हैं। इस बार सुनीता 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रही। सुरक्षा चिंताओं के कारण कई बार विलंबित हुई वापसी यात्रा आखिरकार स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम का पूरी तरह मूल्यांकन के बाद शुरू हुई।

शेष १ पर

राम मंदिर से भी बड़े...

इस ज्ञान के साथ ही भारत की धरती पर सनातन धर्म से टकराव आरंभ हो गया। अशोक के समय यानी कि 272 बीसी से 234 बीसी तक बौद्ध धर्म संकिसा से ग्रीस और ग्रीस से सीरिया तक पहुंच चुका था। ये वही समय था जब पहली बार यूरोप,सेंट्रल,एशिया माइनर और दक्षिण एशिया जैसे दूसरे देशों में पशुओं के लिए चिकित्सालय खोले गए औषधियों के लिए बागानों की स्थापना की गयी। अब समय आया 181 बीसी का। पीपल के बोधि वृक्ष को पुष्यमित्र शुंग ने काट दिया था। इतिहास गवाही देता है कि अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने वाले.. भिक्षुओं के सिर भी काट दिए गए। बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन का खेल तब से ही निरंतर भारत में चल रहा है।

आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जो बिहार के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल बोधगया में पिछ पिछले 12 फरवरी से जारी है।

इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बीटी एक्ट यानी बोधगया टेंपल एक्ट, 1949 ख़त्म किया जाए और महाबोधि मंदिर का पूरा नियंत्रण बौद्धों को सौंप दिया जाए।

दरअसल, बीटी एक्ट यानी बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 भारत सरकार द्वारा पारित एक कानून है, जो महाबोधि मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम बिहार सरकार को यह अधिकार देता है कि वह महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति का गठन करे और मंदिर का संचालन देखें। इस मंदिर के संचालन के लिए मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया। जिसमें 9 सदस्य होते हैं। इस अधिनियम प्रबंधन समिति में हिंदू बहुमत होना आवश्यक है – यानी 9 में से 5 सदस्य हिंदू होंगे। जिलाधिकारी जो हिंदू होता है समिति का अध्यक्ष बनता है। बौद्ध भिक्षु केवल एक सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे अध्यक्ष नहीं बन सकते। यह अधिनियम बौद्धों को उनके ही सबसे पवित्र स्थल का पूर्ण प्रबंधन नहीं देता।

भंते विनाचार्य कहते हैं कि बीटी एक्ट को लेकर बौद्ध भिक्षुओं में काफी नाराजगी है। देश के कई राज्य जैसे उत्तर-प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में इस एक्ट का बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इतना ही नहीं 12 फरवरी से जारी इस प्रदर्शन को अब कई अन्य देशों से भी सपोर्ट मिल रहा है।

अब सवाल उठता है कि इतने लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन पर सरकार क्यों आंख मूंद कर बैठी है ?आखिर कब सरकार इनकी मांगों पर गौर करेगी ?अगर वक्त रहते इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत की बौद्ध देशों में छवि प्रभावित हो सकती है। बौद्ध धार्मिक पर्यटन पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि कई विदेशी बौद्ध श्रद्धालु भारत सरकार से नाराज़ हो सकते हैं। इतना ही नहीं भारत-श्रीलंका और भारत-म्यांमार संबंधों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ये देश बौद्ध धरोहर को लेकर संवेदनशील हैं। और भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर असर पड़ सकता है।

बता दें कि 12 फरवरी से जारी ये आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है। बीटी एक्ट के खिलाफ आंदोलन की जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं। दरअसल, बात 1891 की है, जब श्रीलंका के प्रसिद्ध बौद्ध धर्म प्रचारक अंगारिका धम्मपाल ने पहली बार महाबोधि विहार पर बौद्धों के नियंत्रण की मांग उठाई थी। उस वक्त यह मंदिर हिंदू महंतों के अधीन था, और बौद्धों का मानना था कि उनकी धार्मिक विरासत पर अतिक्रमण हो रहा है। धम्मपाल ने इसके लिए महाबोधि सोसायटी की स्थापना की और ब्रिटिश सरकार से इसकी वापसी की मांग की। हालांकि, उनकी कोशिशें पूरी तरह सफल नहीं हुईं। अब एक बार फिर से आंदोलन ने जोर पकड़ा है। और आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और 20 अप्रैल से दिल्ली से बोधगया तक विरोध प्रदर्शन करेंगे।

महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन को समाप्त करने से पहले दिनकर की ये पंक्तियां कहना वाजिब होगा ,जिसकी गंध महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन से उठने लगी है।

...याचना नही अब रण होगा,
संघर्ष बड़ा भीषण होगा
अब तक तो सहते आए हैं,
अब और नहीं सह पाएंगे,
हिंसा से अब तक दूर रहे,
अब और नही रह पायेंगे,
मारेंगे या मर जायेंगे,
जन जन का ये ही प्रण होगा,
याचना नही अब रण होगा,
संघर्ष बड़ा भीषण होगा।

सवाल यह है कि सालों से जारी ये आंदोलन कब अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? क्या बौद्ध समुदाय को उनकी यह पवित्र धरोहर पूरी तरह वापस मिल पाएगी? यह समय ही बताएगा।

विवादों का अड्डा बना ए आई ग्रोक ...

ग्रोक-3 इसका नवीनतम वर्जन है, जिसे फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया। मस्क के अनुसार, यह पहले की तुलना में 10 गुना अधिक पावरफुल है।ग्रोक शब्द की उत्पत्ति रॉबर्ट ए. हेनलेन के 1961 के साइंस फिक्शन उपन्यास 'स्ट्रेंजर इन ए स्ट्रेंजर लैंड' से हुई है। इसमें ग्रोक का मतलब होता है गहरी सहानुभूति और समझ। ग्रोक के जवाबों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तहलका मचा दिया है। खासतौर पर राजनीतिक सवालों के जवाबों ने इसे सुर्खियों में ला दिया।एक यूजर ने पूछाः "पीएम मोदी के फैलाए गए झूठों की लिस्ट बनाओ।" ग्रोक का जवाब था -काले धन की वापसी, कोविड-19 नियंत्रण और मेक इन इंडिया के दावों को झूठ बताया। एक यूजर ने पूछा "2029 में PM कौन बनेगा ? ग्रोक का जबाव था "यह जनता के फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन राहुल गांधी की पारदर्शिता और जनता के मुद्दों पर काम करने की क्षमता उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है।" एक और सवाल पर ग्रोक ने डोनाल्ड ट्रम्प को पुतिन के प्रभाव में बताया। वहीं, इलॉन मस्क को "अमेरिका के सबसे हानिकारक नागरिक" कह दिया।मोदी बनाम राहुलः जब एक यूजर ने पूछा कि मोदी और राहुल गांधी में कौन बेहतर नेता हैं, तो ग्रोक ने राहुल गांधी को पारदर्शिता और जनता के मुद्दों पर बेहतर बताया। सोनिया गांधी पर फेक न्यूज का जवाबः ग्रोक ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, "सोनिया गांधी कभी बार डांसर नहीं रहीं, बल्कि एक रेस्टोरेंट में अटेंडर के रूप में काम करती थीं।

ग्रोक के इन जवाबों पर बीजेपी समर्थकों ने इसे 'प्रोपेगैंडा टूल' करार दिया, जबकि कांग्रेस समर्थक इसे 'सच बोलने वाला एआई ' बता रहे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में ग्रोक जैसे एआई टूल्स चुनावी बहसों में अहम भूमिका निभा सकते हैं।हालांकि अभी तक भारत सरकार ने ग्रोक पर बैन लगाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक दबाव बढ़ने पर इस पर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल हम यहाँ चर्चा करेंगे पीएम मोदी के कई झूठों के बारे में। यह सब इसलिए कि ग्रोक ने कई मामलों में पीएम मोदी के दावे को गलत बताया है। मोदी के हाल के भाषणों की कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें उनके झूठ के रूप में बताया जा रहा है। अब यह उनके झूठ हैं या फिर जानकारी का अभाव यह फैसला तो जनता ही कर सकती हैं।

नरेन्द्र मोदी ने कभी कहा था कि चीन अपनी जीडीपी का 20 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन भारत सरकार नहीं। हकीकत यह है कि चीन अपनी जीडीपी का महज 3.93 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च करता है। वहीं भारत में एनडीए सरकार के कार्यकाल में शिक्षा पर 1.6 प्रतिशत खर्च हुआ और यूपीए के कार्यकाल में सालाना जीडीपी का 4.04 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हुआ है।.

दूसरा झूठ : मोदी ने एक सभा में भारतीय इतिहास से बिहार के गौरव का उदाहरण बखान करते हुए बताया कि सिकंदर महान को गंगा नदी के तट पर बिहारियों ने हराया था। लेकिन सच यह है कि सिकंदर महान 326 ई.पू. तक्षशिला से होते हुए से पुरु के राज्य की तरफ बढ़ा जो झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। राजा पुरु से हुए घोर युद्ध के बाद वह व्यास नदी तक पहुंचा, परन्तु वहां से उसे वापस लौटना पड़ा। उसके सैनिक मगध (वर्तमान बिहार) के नन्द शासक की विशाल सेना का सामना करने को तैयार न थे। इस तरह से सिकंदर पंजाब से ही वापस लौट गया था।

तीसरा झूठ : मोदी ने बिहार के गौरवशाली इतिहास का बखान करते हुए कहा कि विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला या टेक्सिला विश्वविद्यालय बिहार में था।सच तो यही है कि तक्षशिला प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है।

चौथा झूठ : एनडीए की कार्यकाल में भारत की विकास दर 8.4 प्रतिशत थी। लेकिन सच तो यही है कि एनडीए के कार्यकाल में भारत की विकास दर मात्र 6 प्रतिशत थी।पांचवा झूठ -गुजरात में देश में सबसे अधिक विदेशी पूंजी निवेश होता है। इसकी सच्चाई यह है कि आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 से 2011 तक गुजरात में 7.2 बिलियन डॉलर का विदेशी पूंजी निवेश हुआ है, जबकि इसी अवधि में महाराष्ट्र में 45.8 बिलियन डॉलर और दिल्ली में 26 बिलियन डॉलर का विदेशी पूंजी निवेश हुआ है।

छठा झूठ : नर्मदा पर बांध बनने पर लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी।इसकी सच्चाई यह है कि अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी प्रदेश में नदियों पर बांध बनने से मुफ्त में लोगों को बिजली मिली हो। राष्ट्रीय बिजली नियामक आयोग के अनुसार बिजली के लिए पैसा देना ही होगा।और सातवां झूठ : मोदी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पटना भाषण के बाद सरकार ने टीवी मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की नीयत से मीडिया एडवाइजरी जारी की है। इस मामले हकीकत इससे उलट है। दरअसल, नरेन्द्र मोदी ने 27 अक्टूबर को पटना में भाषण दिया था, जबकि सूचना प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी इससे एक सप्ताह पहले 21 अक्टूबर को ही जारी कर दी गई थी। यह एडवाइजरी सूचना प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर भी मौजूद है।

एक बड़े अखबार के इंटरव्यू के बाद एक और 'झूठ' सुर्खियों में आया था, जिसमें मोदी ने कहा था कि सरदार पटेल की अंत्येष्टि में पंडित नेहरू शामिल नहीं हुए थे। हालांकि इस अखबार ने ही इस बात का खंडन कर दिया कि मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये सभी बातें तो बहुत पहले की है लेकिन हाल के वर्षों में भी मोदी ने कई तरह की ऐसी बातें कहीं है जो सच के करीब नहीं है। अब तो ग्रोक ने पीएम मोदी के झूठ को जनता के सामने ही रख दिया है।

स्टारलिंक की भारत्त...

विलियम्स और विलमोर को लेकर स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल ने 18 मार्च को सफलतापूर्वक आईएसएस से अनडॉक किया, और लगभग 17 घंटे की यात्रा के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, जहां उसने पैराशूट की मदद से फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित लैंडिंग की। अब जब वे लौट आए हैं, तो अंतरिक्ष यात्री चिकित्सकीय निगरानी और रिकवरी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। स्वास्थ्य जांच के बाद, वे अपने परिवारों से मिलेंगे और गुरुत्वाकर्षण, ताजी हवा और घर के आराम का आनंद लेंगे।

पिछले वर्ष सोयुज कैप्सूल के जरिए तीन क्रू सदस्यों को धरती पर आने में साढ़े तीन घंटे ही लगे थे। लेकिन सुनीता को लौटने में 17 घंटे क्यों लग गए यह बड़ा सगवाल है ? बता दें कि सायुज एक सीध और तेज गति से धरती पर वापसी करता है, जिसके चलते आइएसएस से अलग होने के बाद यान की पृथ्वी के वायुमंडल में जल्द एंट्री हो जाती है, जबकि ड्रेगन अपेक्षाकृत धीमी और नियंत्रित गति से वापसी करता है। यह सीधे आने की बजाय पृथ्वी की परिक्रमा करता है और अनुकूल समय और स्थान चुनकर नीचे की ओर मुड़ता है। लैंडिंग के लिए ड्रैगन कैप्सूल को सटीक अलायमेंट की आवश्यकता होती है। आइएसएस पृथ्वी से करीब 420 किमी ऊपर है।

अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाले स्पेसक्राफ्ट की गति 28 हजार प्रति घंटे की गति समुद्र में उतरते वक्त 32 किमी प्रति घंटे ही रह जाएगी। सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान रहता है, इस दौरान घर्षण से बचाना बड़ी चुनौती है और स्पेसएक्स ड्रैगन की तैयारी बेहतर मानी जाती है।

यह भी बता दें कि सायुज हमेशा जमीन पर उतरता है, जबकि क्रू ड्रैगन समुद्र में स्प्लेशडाउन करता है। मौसम और समुद्री परिस्थिति जांचने के लिए भी क्रू ड्रैगन अतिरिक्त समय लेता है।सुनीता विलियम्स की वापसी पर नासा ने स्पेसएक्स को धन्यवाद दिया। नासा ने कहा कि इस मिशन में कई चुनौतियां थी। लेकिन ये सफल रहा।

करीब 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स के धरती पर लौटने के बाद भारत में जश्न का माहौल है। सुनीता के पैतृक गांव झूलासन में लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए पटाखे फोड़े। बता दें कि सुनीता गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव की रहने वाली है। उनका परिवार 60 के दशक में ही अमेरिका चला गया था।

बता दें कि सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष मिशन 5 जून 2024 को शुरू हुआ था, जो केवल 8 दिनों का था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण वे और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हेग और रोस्कोस्मोस 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहे।

पूर्व अमेरिकी नौसैन्य कप्तान सुनीता विलियम्स (59) का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड (ओहियो) में हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाणा जिले के झूलासन से ताल्लुक रखते हैं और मां उर्सुलाइन बोनी पांड्या स्लोवेनिया से हैं। अपनी बहु-सांस्कृतिक जड़ों पर गर्व करते हुए विलियम्स अपने साथ अंतरिक्ष में अपनी विरासत के प्रतीक ले जा चुकी हैं, जिनमें समोसे, स्लोवेनियाई ध्वज और भगवान गणेश की मूर्ति शामिल हैं।

सुनीता विलियम्स को बचपन से ही विज्ञान में रुचि थी, लेकिन उनका सपना पशु चिकित्सक बनना था। उनके भाई जय का अमेरिकी नौसेना अकादमी में चयन हुआ था और वहां जाने के बाद सुनीता ने नौसेना अधिकारी बनने का सपना देखा। यह वह समय था जब महशूर अभिनेता टॉम क्रूज अभिनीत 'टॉप गन' धूम मचा रही थी। जब विलियम्स को नौसेना विमानन प्रशिक्षण कमान में शामिल होने का अवसर मिला तो वह लड़ाकू विमान उड़ाना चाहती थीं लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर का विकल्प चुनना पड़ा। वह 1989 में नौसेना एविएटर बनीं और उन्होंने नॉरफ़ॉक, वर्जीनिया में 'हेलिकॉप्टर कॉम्बैट सपोर्ट स्क्वाड्रन 8' में सेवा दी, इसके अलावा उनकी तैनाती 'डेजर्ट शील्ड' और 'ऑपरेशन प्रोवाइड कम्फर्ट' के समर्थन में भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में भी की गई।

विलियम्स ने सैनिकों और मानवीय सहायता के परिवहन में अहम भूमिका निभाई तथा उनके नेतृत्व कौशल और विषम परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता ने उन्हें भविष्य के अंतरिक्ष यात्री के रूप में अग्रसर किया। विलियम्स को 1998 में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना और उन्होंने 'जॉनसन स्पेस सेंटर' में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भी काम किया।

सुनीता विलियम्स 9 दिसंबर 2006 को 'अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी' पर सवार होकर अपने पहले मिशन पर रवाना हुईं और आईएसएस अभियान 14 और 15 में शामिल होकर 195 दिनों के लिए कक्षा में रहीं। विलियम्स 17 जुलाई 2012 को रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज पर सवार होकर अंतरिक्ष स्टेशन पर चार महीने के प्रवास के बाद वापस आईं और 19 नवंबर को पृथ्वी पर लौट आईं। वह 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति बनीं।

सुनीता विलियम्स ने अपने अंतरिक्ष मिशन के तुरंत बाद 2007 और 2013 सहित कम से कम तीन बार भारत का दौरा किया है और उन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विलियम्स को एक पत्र लिखकर उन्हें भारत की बेटी बताया था और देश आने का निमंत्रण दिया था। उनके पति माइकल जे. विलियम्स संघीय पुलिस अधिकारी हैं।

न्यू देहली पोस्ट
30 मार्च 2025
संपादकीय कार्यालय : मुद्रक व प्रकाशक आशीष कुमार द्वारा विभा पब्लिकेशन डी-160 बी, सेक्टर-7, नोएडा से मुद्रित एवं 262ए, सेक्टर-4, वैशाली गाजियाबाद से प्रकाशित। RNI NO. UPHIN/2013/49239
संपादक : आशीष कुमार, **प्रसार प्रबंधक** : दशरथ सिंह
Postal registration Number: UP/GBD-181/2013-15, **हमसे संपर्क करें** : postnewdelhi@gmail.com

न्यू देहली पोस्ट

संपादकीय

सुनीता विलियम्स की वापसी विज्ञान की जीत

अंतरिक्ष की दुनिया एक अद्भुत दुनिया जहाँ कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ भी है। कह सकते हैं वहां सब कुछ शून्य है और शून्य से आगे भी। इस अद्भुत संसार से निकलकर सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर 19 मर्च के तड़के धरती पर पहुँच गए। वे स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रही है। बता दें कि ये दोनों अंतरिक्ष यात्री सिर्फ आठ दिनों के लिए अन्तरिक्ष में गए थे लेकिन कुछ तकनीकी मुश्किलों के चलते उन्हें 9 महीने तक वहां रुकने पर विवश होना पड़ा। पृथ्वी से औसतन लगभग 400 किलोमीटर ऊपर नितांत निर्जन व निर्वात, शून्य गुरुत्वाकर्षण, करोड़ों किलोमीटर तक अंतरिक्ष में पृथ्वी व उसके चंद्रमा के बगैर माइनस 121 डिग्री सेल्सियस से लेकर माइनस 157 डिग्री सेल्स. तापमान में सुनीता विलियम्स व बुच विल्मोर ये यात्री थे, जिन्होंने नयी-नयी तकनीकी दिक्कतों को अपने साहस, धैर्य और ज्ञान से परास्त करते हुए पृथ्वी पर वापसी कर खगोल विज्ञान के इतिहास में अपने नाम के अलग अध्याय लिख दिये हैं। सुनीता के प्रति भारतीयों का लगाव स्वाभाविक है क्योंकि उनकी जड़ें इसी देश की हैं, परन्तु इस मायने में उनका नाम ऊपर लिखा जायेगा कि वे पहली ऐसी यात्री बन गयी हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की तीन बार यात्राएं कीं। इसके साथ ही वे उस क्लब में शामिल हो गयी हैं जिन्होंने 600 से ज्यादा दिन घने काले अंतरिक्ष में बिताये हैं जो अनंत है, अपार है, अबूझ व अल्पज्ञात भी।

हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब वर्ष आंकी गयी है। लगभग 5 अरब साल पहले तैरती धूल और हीलियम व हाइड्रोजन गैसों से सूर्य बना और पृथ्वी तकरीबन 4.6 अरब साल पहले अस्तित्व में आई। हमारे सौरमंडल में ज्यादातर ग्रहों व क्षुद्र ग्रहों से बने असंख्य स्पेस ऑब्जेक्टस बने हैं जो परस्पर टकरावों का प्रतिफल हैं। कोई भी वस्तु कब किससे आकर टकरा जाये, कहा नहीं जा सकता- ऐसे खतरे के बीच यह मनुष्य का साहस व ज्ञान ही है जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में टिके रहने का संकल्प प्रदान करता है। वैज्ञानिकों के साहस, बलिदान और जिज्ञासा ने ही विज्ञान को आज यहां तक पहुंचाया है। भारत में पिछले कुछ समय से वैज्ञानिक और तकनीकी कौतूहल नाम का तत्व खत्म हो रहा है; या कहें कि खत्म किया गया है। ऐसे में ज्यादातर भारतीय दुनिया में हो रहे वैज्ञानिक व तकनीकी विकास से अनभिज्ञ हैं। सामान्य युवाओं और छात्रों को पूछिये कि सुनीता विलियम्स का क्या माजरा है, तो वे जवाब नहीं दे पाएंगे। न उन्हें शून्य गुरुत्वाकर्षण का पता है न अंतरिक्ष का रंग ज्ञात है। बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल से अपरिचित वे यह भी नहीं जानते कि अंतराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन क्या है और वह कितनी ऊंचाई पर कार्यरत है। उसका उद्देश्य क्या है और अब तक उसने क्या किया है। यही ज्ञान वैज्ञानिक तरक्की की दौड़ शुरू करने वाली वह रेखा है जिसमें तमाम विकसित देश एक-दूसरे के साथ होड़ लगा रहे हैं जबकि भारत ठीक विपरीत दिशा में भाग रहा है- अज्ञानता की तरफ़।

भारत के चार अंतरिक्ष यात्री मिशन गगनयान के लिए तैयार

न्यूज़ डेस्क

सुनीता विलियम्स की तरह ही भारत के चार अंतरिक्ष यात्री मिशन गगनयान के लिए तैयार हैं। बता दें कि गगन यान की पूरी तैयारी हो चुकी है और अगले साल की शुरुआत में यह मिशन शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इसी साल के अंत तक आखिरी परिक्षण उड़ान के तहत महिला रोबोट व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।

मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों को सार्वजनिक चमक-दमक से दूर रखा गया था ताकि किसी तरह ध्यान नहीं भटके क्योंकि वे कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजर रहे थे।उन्होंने कहा, ''गगनयान को भेजने की तैयारी लगभग हो चुकी है। आखिरी परीक्षण उड़ान, जो एक प्रकार का 'ड्रेस रिहर्सल' होगा, के तहत महिला रोबोट 'व्योममित्र' इस साल के आखिर में अंतरिक्ष में जाएगी और सुरक्षित तरीके से लौटेगी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गगनयान अंतरिक्ष में जाएगा।''

बता दें कि गगनयान के लिए चार अंतरिक्ष यात्री चुन लिए गए हैं और उनका विधिवत प्रशिक्षण भी लगभग पूरा हो चुका है। मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया है। केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों में से शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा में अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएंगे। सिंह ने कहा, ''इनमें एक विंग कमांडर शुक्ला हैं जो अब ग्रुप कैप्टन शुक्ला हैं। इसलिए उनका नाम थोड़ा व्यापक रूप से पहचाना गया।'' जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान-4 के संदर्भ में बताया कि यह मूलतः चंद्रमा से नमूने लाने के लिए है, लेकिन वो उन सभी प्रक्रियाओं को अंजाम देगा जो आने वाले मिशन के लिए अनिवार्य रहेंगी। उन्होंने कहा कि चंद्रयान से आगे के सभी मिशन के लिए अनुभव मिलेगा और इसमें 'डॉकिंग' तथा 'अनडॉकिंग' के अनुभव भी मिलेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि 2027 में चंद्रयान-4, 2028 में शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने के लिए 'वीनस मिशन' भेजा जाएगा, 2035 में भारत अंतरिक्ष स्टेशन खोला जाएगा और 2040 में भारतीय मूल का व्यक्ति चांद की धरती पर उतरेगा। सिंह ने यह भी बताया कि देश का चौथा अंतरिक्ष लांच पैड तमिलनाडु के तुतिकोरिन में बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ''1979 में इसरो की स्थापना के कई वर्ष बाद देश का पहला लांच पैड बनाया गया था। इसके दस वर्ष बाद दूसरा लांच पैड श्रीहरिकोटा में तैयार किया गया।'' सिंह ने बताया, ''सरकार ने श्रीहरिकोटा में तीसरा लांचपैड बनाना शुरू कर दिया है और चौथा लांच पैड तमिलनाडु के तुतिकोरिन में बनाने की शुरुआत हो गई है।''

मोदी सरकार के खिलाफ अदालत पहुंची एलन मस्क की कंपनी

न्यूज़ डेस्क

ग्रोक एआई द्वारा यूजर से पूछे गए सवाल और ग्रोक के सटीक और विश्लेषण से भरे जवाब से मोदी सरकार और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीजेपी को लग रहा है कि ग्रोक उसके खेल को ओपन कर रहा है और पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक को झूठा बता रहा है। जाहिर है बीजेपी को लग रहा है कि ग्रोक पीएम मोदी के इकबाल को कमजोर करने का प्रयास कर जनता में उनकी छवि को ख़राब कर रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो बीजेपी का चुनावी अभियान कमजोर हो सकता है।

अब इस बढ़ते विवाद के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स कॉर्प से उसके एआई चैटबॉट ग्रोक को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है । ग्रोक, जिसे एक्स की मूल कंपनी एक्स एआई ने विकसित किया है, हाल ही में कुछ सवालों के जवाब में अभद्र भाषा और गालियों का इस्तेमाल करता पाया गया। भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए कंपनी से जवाब तलब किया है। इससे पहले भी साल 2022 में सरकार ने धारा 69ए के तहत एक्स को कुछ कंटेंट हटाने का निर्देश दिया था, जिसे लेकर कंपनी और सरकार के बीच तनाव देखा गया था।

अब एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) को चुनौती दी गई है। कंपनी का आरोप है कि यह नियम सरकार को अनुचित और गैरकानूनी सेंसरशिप लागू करने की शक्ति देता है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन पर गंभीर असर पड़ रहा है। यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया है, जब भारत सरकार ने एक्स के एआई चैटबॉट ग्रोक के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं।

आईटी एक्ट की धारा 79(3)(बी) के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह कुछ खास परिस्थितियों में इंटरनेट पर मौजूद कंटेंट को हटाने या ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। हालांकि, एक्स कॉर्प का दावा है कि सरकार इस प्रावधान का दुरुपयोग कर रही है। कंपनी के मुताबिक, कंटेंट हटाने के लिए सरकार को लिखित में ठोस कारण बताना चाहिए, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का मौका देना चाहिए और इस फैसले को कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। एक्स ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत सरकार ने इनमें से किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

रिपोर्ट के अनुसार, एक्स कॉर्प ने तर्क दिया है कि सरकार धारा 79(3)(बी) की गलत व्याख्या कर रही है और ऐसे आदेश जारी कर रही है जो धारा 69ए के नियमों के अनुरूप नहीं हैं। धारा 69ए में स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों का जिक्र है, जिनमें सरकार कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा। कंपनी ने 2015 के श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए सेंसरशिप के लिए सख्त दिशा-निर्देश तय किए गए थे।

एक्स कॉर्प ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार के आदेश पारदर्शिता की कमी को दर्शाते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करते हैं। कंपनी का मानना है कि धारा 79(3)(बी) के तहत जारी होने वाले अस्पष्ट और मनमाने आदेश प्लेटफॉर्म की स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हैं। एक्स ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने सायोग पोर्टल के जरिए कंटेंट ब्लॉक करने की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है, जिससे प्लेटफॉर्म के लिए नियमों का पालन करना मुश्किल हो गया है।

कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर इस याचिका पर अगली सुनवाई 27 मार्च 2025 को होनी है। यह मामला न केवल एक्स कॉर्प और भारत सरकार के बीच टकराव को दर्शाता है, बल्कि डिजिटल सेंसरशिप, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियों जैसे बड़े मुद्दों पर भी बहस छेड़ सकता है। जहां सरकार इसे नियमों के अनुपालन और राष्ट्रीय हितों की रक्षा का मामला बता रही है, वहीं एक्स इसे अपनी स्वायत्तता और यूजर्स के अधिकारों पर हमला मान रहा है।

इस मामले का नतीजा न सिर्फ भारत में सोशल मीडिया के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारों के रिश्तों पर असर डाल सकता है। देखना यह है कि कोर्ट इस जटिल मसले पर क्या फैसला सुनाता है।

मनुस्मृति और सनातनी पाखंड पर सरला गुप्ता का हमला

उपनयन से लेकर अंतिम संस्कार के जरिए पुरुषवादी सत्ता को चुनौती

न्यूज़ डेस्क

हिन्दू धर्म और सनातनी जीवन पद्धत्ति मनुस्मृति के साथ ही वेद -पुराणों से संचालित होती है। सनातनी लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में इन धार्मिक ग्रंथों में बहुत कुछ कहा गया है। सनातनी व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति को भी रेखांकित किया गया है और महिलाओं द्वारा पूजा पाठ करने से लेकर अंतिम संस्कार के बारे में भी बहुत सी बातें कही गई है। खासकर मनुस्मृति ,वेद,बृहस्पति स्मृति ,नारद स्मृति और गरुड़ पुराण में महिलाओं के लिए वेद ज्ञान ,,कर्मकांड और अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने और नहीं लेने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। कुछ निषेध भी हैं और कई बातों पर चुप्पी भी है।

लेकिन आज का समय बदल गया है। सनातनी परम्परा या तो लचीला हो गई है या फिर धार्मिक ग्रंथों में जो बाते कही गई है उसके खिलाफ आज बहुत से काम होते दिख रहे हैं और कथित सनातनी महंथ चुप्पी साधे हुए हैं। इस चुप्पी के पीछे का रहस्य जो भी हो लेकिन एक सवाल तो उठ ही रहा है कि अंधभक्त सनातनियों को केवल मुसलमानो के खिलाफ हिन्दू राष्ट्र ही चाहिए या फिर सनातन धर्मो को आगे बढ़ाने वाले धार्मिक ग्रंथों में दर्ज बातों की स्वीकृति भी चाहिए ? लेकिन उत्तर देगा कौन ?

राजस्थान के उदयपुर की सरला गुप्ता सनातनी परंपरा को चुनौती दे रही है और उपनयन संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार को अंजाम दे रही हैं । देश की यह पहली ऐसी महिला हैं जो अब तक 50 से ज्यादा विवाह संस्कार को पूर्ण करा चुकी है और लगभग 70 से ज्यादा मृतक का अंतिम संस्कार भी करा चुकी है। और आज भी वह पुरुष सत्तातमक समाज और सनातनी परंपरा के खिलाफ जाकर इन कार्यों को करती जा रही है।

सरला गुप्ता न्यू दिल्ली पोस्ट को कहती हैं कि ''वह किसी को कोई चुनौती नहीं दे रही है। वह तो केवल अपने काम को कर रही है। जहाँ तक सनातन धर्म और मनुस्मृति में कर्मकांडो से महिलाओं को वंचित करने की बात कही जा रही है वह भी सच नहीं है। मूल मनुस्मृति में महिलाओं पर ऐसा कोई रोक नहीं है लेकिन बाद के वर्षों में उसमे कई बातें स्त्रियों के खिलाफ जोड़ी गई। जो कही से उचित नहीं है। आज जब महिलाये हर काम पुरुषों के साथ कर सकती हैं तो कर्मकांड क्यों नहीं कर सकती ? अब समय बदल गया है। ''

गौरतलब है कि सरला गुप्ता 65 साल की है। वे कहती हैं कि यह पांडित्यपूर्ण कार्य को मैंने चुनौती के रूप में। 2016 से उन्होंने विवाह -उपनयन संस्कार को करना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने वाकायदा कई विद्वानों से प्रशिक्षण भी लिया। पढ़ाई की और इसकी समझने का काम। किया। इसके बाद कोरोना के चारो तरफ लाशें पड़ी हुई थी तब हमने दाह संस्कार कराने का भी। इसके तरीके को समझा और इससे सम्बंधित कर्मकांड को समझकर इसे आगे बढ़ाने का काम किया।

और यह सब वह सेवा भाव से कर रही है और आज की नयी पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रही है। बड़ी बात तो यह है कि सरका गुप्ता इन कर्मकांडो से जो आय अर्जित करती हैं वह सब अनाथ और गरीब बच्चो की पढ़ाई पर खर्च कर रही है और राजस्थान के कई स्कूलों को सहयोग दे रही है। मनुस्मृति में कई श्लोक ऐसे हैं जो स्त्रियों के अधिकारों और उनके धार्मिक कार्यों में भाग लेने को लेकर चर्चा करते हैं। हिंदू रीति-रिवाजों में "संस्कार" एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, और मनुस्मृति में स्त्रियों के कुछ संस्कारों को करने की अनुमति न होने का उल्लेख मिलता है।मनुस्मृति (9.18) में कहा गया है कि

"पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः, न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति॥"

अर्थात एक स्त्री को बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र द्वारा संरक्षित रहना चाहिए। इससे यह संकेत मिलता है कि स्त्रियों को धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता सीमित रूप से दी गई थी।

इसी मनुस्मृति के (5.155) में कहा गया है कि "न स्त्री स्वाधीनता, न उपनयनसंस्कारः।"अर्थात स्त्रियों को उपनयन संस्कार (जो वेदाध्ययन और यज्ञ करने का अधिकार देता है) नहीं प्राप्त होता। इसी कारण उन्हें वेद मंत्रों के साथ यज्ञ, श्राद्ध और अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी गई है।

मनुस्मृति (2.66) में यह भी कहा गया है कि "त्रयो वर्णा द्विजातयः, स्मृताः शुद्धिकर्मणि।
शूद्राणां च स्त्रियां चैव, नैव संस्कारो विधीयते॥"
अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही शुद्धि और संस्कार करने का अधिकार है, लेकिन शूद्रों और स्त्रियों को संस्कार करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

मनुस्मृति यह भी कहता है कि उपनयन संस्कार ,श्राद्ध कर्म ,अग्निहोत्र यज्ञ और सन्यास संस्कार स्त्रियों के लिए वर्जित हैं। " ऋग्वेद में महिलाओं को युद्ध में भाग लेने तथा संपत्ति ग्रहण करने की स्वतंत्रता दी गई थी। अगर ऋग्वेद के पंचम, षष्ठम वशों का विश्लेषण करें तो यहां महिलाओं के लिए कई तरह के कार्य नियत किए गए हैं। किंतु उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों का अध्ययन करने पर महिलाओं की अवनत होती अवस्था की जानकारी म इल्ति है।

स्मृतियों के काल में महिलाओं के लिए कई तरह के निषेध नियम आरोपित किए गए। महर्षि याज्ञवल्क्य तथा गार्गी संवाद में ऋषि का रुष्ट होकर गार्गी को चेतावनी देना यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि तत्कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय होनी शुरू हो चुकी थी। उन्हें शास्त्रार्थ करने का अधिकार नहीं रह गया था तथा भूमि पर से भी उनका अधिकार छीन लिया गया था।

किसी भी इंसान के जीवन-मरण सम्बंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मिलता है। यह एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है जो वेदों की परंपरा का ही हिस्सा है। हालांकि, इस ग्रंथ में महिलाओं और दाह संस्कार जैसी किसी व्यवस्था का जिक्र नहीं है। इसलिए जाहिर तौर पर, गरुड़ पुराण या उस मामले के लिए कोई भी अन्य धार्मिक ग्रंथ, महिलाओं को दाह संस्कार करने से स्पष्ट रूप से मना नहीं करता है। नारी का मन कोमल इसलिए श्मशान वर्जित बुद्ध कालीन भारत में महिलाओं के लिए निषेध नियम कठोर होने लगे थे। बाद के कालों में सबसे बड़ी बात शव के अंतिम संस्कार के अधिकार से जुड़ी जब स्त्री को इसके लिए वर्जित घोषित कर दिया गया। इसके पौराणिक व वैदिक साक्ष्य तो नहीं है कि कब ऐसा किया गया किंतु स्मृतिकारों ने इस पर अधिक बल दिया कि स्त्री को श्मशान का रुख नहीं करना चाहिए।

अब समाज में महिला पंडित व पुजारी का भी प्रचलन महिलाएं मुखाग्नि या अंतिम संस्कार कर सकती है या नहीं कर सकती है, इन सब सवालों को पीछे छोड़ते हुए आज की महिला पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में भी दखल देने लगी है। आज अनेक शहरों में महिला पंडित व पुजारी देखी जा सकती हैं। केरल में तो अयंगर महिलाएं जनेऊ धारण करती है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कराती हैं। हाल फिलहाल महिलाएं निधन के बाद होने वाले कर्मकांड नहीं कराती। लेकिन अब सरला गुप्ता जैसी महिला इस काम को आगे बढ़ा रही है।

राजस्थान के जोधपुर शहर में तो एक महिला श्मशान का भी संचालन करती है, जब कपाल क्रिया के बाद सभी परिजन चले जाते हैं तो वह शव के पूरे दहन की प्रक्रिया संपन्न करती है। उदयपुर की सरला गुप्ता जो भी कर रही है वह किसी क्रांति से कम नहीं। कथावाचक और धर्म आख्याता के रूप में महिलाये आज बड़ी संख्या में खड़ी होकर पुरुषों को चुनौती दे रही है लेकिन शुभ संस्कार से लेकर अन्तिंम संस्कार कराने वाली सरला गुप्ता के प्रण कई सवालों को भी खड़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सनातनी और हिन्दू धरम का ढिंढोरा पीटने वाले लोग क्या यह बता पाएंगे कि मनुस्मृति से लेकर बाकी धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं के लिए जो वर्जनाये की गई ,उसके बारे में सनातनी नेता और धार्मिक खिलाड़ी क्या राय रखते हैं ? क्या संघ और बीजेपी के लोग यह बता सकते हैं कि जिस मनुस्मृति के आधार पर वे सनातन भारत बनाने की मंशा रखते हैं उसमे सरला गुप्ता के कृत्य को किस रूप में लेते हैं ?क्या वे बता सकते हैं कि जो मनुस्मृति और बाकी धर्म ग्रन्थ कहते हैं ,वह सही है या फिर सरला गुप्ता जो कर रही है वह सब ठीक और जायज है ?

तुषार गांधी ने खोल दी संघ और बीजेपी की पोल !

न्यूज़ डेस्क

तुषार गांधी के खिलाफ बीजेपी और संघ के लोगों द्वारा किये गए विरोध प्रदर्शन कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उनकी मानसिकता महात्मा गांधी की हत्या करने वालों से अलग नहीं है। यह बेहद निंदनीय है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने वाली हरकतों को लोकतांत्रिक समाज में अनुमति नहीं दी जा सकती। ये शब्द हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के।

दरअसल पिछले दिनों केरल में ही महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा था कि ''कांग्रेस नीत यूडीएफ और माकपा नीत एलडीएफ का केरल में एक-दूसरे से लड़ने का लंबा इतिहास रहा है। यूडीएफ और एलडीएफ को यह समझने की जरूरत है कि भाजपा-आरएसएस के रूप में एक बहुत खतरनाक और कपटी दुश्मन केरल में प्रवेश कर चुका है। दोनों राजनीतिक मोर्चों को यह याद रखना होगा कि भारत के सामाजिक ताने बाने की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। उनके राजनीतिक हित चाहे जो भी हों, इस समय यह कम महत्वपूर्ण है।'' तुषार ने आगे कहा, आरएसएस अंग्रेजों से भी अधिक खतरनाक है। अंग्रेजों ने शासन करना चाहा था, लेकिन वर्तमान खतरा हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। आरएसएस देश की आत्मा को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। हमें उनसे डरना चाहिए। अगर आत्मा चली गई तो सब कुछ

चला जाएगा।' यह घटना बीते बुधवार की है। इसके बाद तुषार गाँधी के खिलाफ बीजेपी और संघ के लोगों ने खूब नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। घटना के अगले दिन बृहस्पतिवार को केरल पुलिस ने इस मामले में भाजपा और आरएसएस के पांच कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैरकानूनी सभा, दंगा और गलत तरीके से बाधा डालने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। हालांकि, इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बता दें कि तुषार गांधी , दिवंगत गांधीवादी पी. गोपीनाथन की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए बुधवार को तिरुअनंतपुरम में थे।

अब तुषार गाँधी के इस बयान के बाद देश के भीतर एक विवाद खड़ा हो गया है और उन्हें गिरफ्तार करने से लेकर माफ़ी मांगने की मांग की जा रही है। लेकिन तुषार गाँधी अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं और माफ़ी मांगने से इंकार कर रहे हैं। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने साफ कहा कि वह अपने हालिया बयानों को वापस नहीं लेंगे और न ही माफी मांगेंगे। गांधी ने कहा, 'मैंने जो कहा, उसमें कोई बदलाव नहीं करूंगा और न ही माफी मांगूंगा। इस घटना ने मेरी हिम्मत और बढ़ा दी है। हमें अब आजादी की लड़ाई से भी ज्यादा जरूरी लड़ाई लड़नी है। हमारा एक साझा दुश्मन है – संघ, जिसे बेनकाब करना जरूरी है।' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें डर है कि 'मेरे परदादा (महात्मा गांधी) के हत्यारों के वंशज कहीं गांधी जी की मूर्ति पर भी गोलियां न चला दें, क्योंकि वे यही करने के आदी हैं।'

उधर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन ने तुषार गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 'वह सिर्फ संयोग से गांधी परिवार में पैदा हुए हैं और महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।' इस दौरान उन्होंने तुषार गांधी की गिरफ्तारी की मांग भी की। उन्होंने यह भी कहा कि 'जो लोग तुषार गांधी को प्रतिमा अनावरण के लिए बुला रहे थे, शायद उन्हें उनके विचारों के बारे में पता नहीं था।' अब यह राजनीति आगे कहाँ तक जाती है इसे देखना होगा लेकिन तुषार गाँधी ने जिस अंदाज में बीजेपी और संघ पर हमला किया है उससे संघ तिलमिला गया है।

न्यू देहली पोस्ट

पीएम मोदी की योजना के खिलाफ खड़े हुए पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई

राजनीतिक डेस्क

देश के सीजेआई रहते हुए अपने कुछ फैसलों के लिए आम लोगों में बदनाम हुए रंजन गोगोई भले ही मोदी की कृपा से राज्य सभा में चले गए लेकिन अब जब उनका टर्म ख़त्म होने वाला है तब वे एक बार फिर से मोदी की एक देश एक चुनाव वाली योजना के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं। उन्होंने इस योजना पर अपनी प्रतिक्रया व्यक्त की है। बता दें कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई हाल ही में प्रस्तावित 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पर चर्चा करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित हुए। सत्र के दौरान, उन्होंने कुछ प्रावधानों, विशेष रूप से चुनाव आयोग को व्यापक अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधानों के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त कीं, और सुझाव दिया कि उन्हें संवैधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

भारतीय जनता पार्टी के सांसद पी.पी. चौधरी के नेतृत्व वाली जेपीसी संविधान विधेयक, 2024 की जाँच कर रही है। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और संबंधित लागतों को कम करना है।समिति को संबोधित करते हुए गोगोई ने शक्ति संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ऐसे प्रावधानों के प्रति आगाह किया जो संभावित रूप से चुनाव आयोग को अनियंत्रित अधिकार प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे खंड न्यायिक जाँच का सामना नहीं कर सकते हैं। विशेष रूप से उन्होंने प्रस्तावित विधेयक की धारा 82ए की ओर इशारा करते हुए इसे संवैधानिक जनादेशों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधनों की सिफारिश की।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अंतर्दृष्टि एक निर्णायक क्षण में आई है, क्योंकि राष्ट्र एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता और निहितार्थों पर बहस कर रहा है। समर्थकों का तर्क है कि इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लागत बचत होगी, चुनाव संबंधी व्यवधानों की आवृत्ति कम होगी और सरकारों को निरंतर चुनाव प्रचार के बजाय शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। हालांकि, आलोचक संघवाद के संभावित क्षरण के बारे में चिंता जताते हैं। उनका तर्क है कि एक साथ चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों को दबा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आख्यान प्रवचन पर हावी हो सकते हैं, जिससे स्थानीय चिंताएं हाशिए पर चली जाएंगी। इसके अतिरिक्त, भारत के विशाल और विविध मतदाताओं को देखते हुए, इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने की तार्किक चुनौतियों के बारे में आशंकाएं हैं।

समिति के साथ बातचीत के दौरान गोगोई ने नागरिकों के मतदान अधिकारों पर विधेयक के प्रभाव से संबंधित प्रश्नों को भी संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून मतदाताओं के मतदान के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि एक एकीकृत चुनावी कार्यक्रम स्थापित करने का प्रयास करता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदान के अधिकार के लिए किसी भी कथित खतरे से व्यापक विरोध और संभावित कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

जनता को जोड़ने और विभिन्न प्रकार की राय एकत्र करने के प्रयास में, संसदीय पैनल ने एक समर्पित वेबसाइट शुरू करने की योजना की घोषणा की है। यह मंच नागरिकों से सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित करेगा। यह सुनिश्चित करते हुए कि चर्चा में समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण शामिल हों। यह पहल पारदर्शिता और सहभागी लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे हितधारकों को प्रस्तावित चुनावी सुधारों के बारे में अपना समर्थन, चिंताएँ या सुझाव देने की अनुमति मिलती है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव कई वर्षों से चर्चा का विषय रहा है। ऐतिहासिक रूप से, भारत ने 1967 तक एक साथ चुनाव कराए, जिसके बाद विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण यह चक्र बाधित हो गया। प्रस्ताव के अधिवक्ताओं का मानना है कि मूल प्रणाली पर वापस लौटने से अधिक स्थिर शासन और संसाधनों का कुशल उपयोग होगा। हालांकि, इस तरह के महत्वपूर्ण बदलाव को लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। विधेयक संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिससे यह सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता होती है कि लोकतंत्र और संघवाद के मूलभूत सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए। गोगोई जैसे कानूनी दिग्गजों द्वारा उठाई गई चिंताएँ एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती हैं जो चुनावी सुधारों को आगे बढ़ाते हुए संस्थागत अखंडता की रक्षा करता है।

इंडस वैली रिपोर्ट : इंडिया के भीतर तीन इंडिया

न्यूज़ डेस्क

ब्लूम वेंचर्स की इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 में कुछ ऐसी बातें सामने आयी है जो मोदी सरकार के तमाम आर्थिक दावे की पोल खोलती है। मजे की बात तो यह है कि कदेश की बड़ी बीजेपी समर्थित आबादी जिसे अंधभक्त कहा जाता है ,वह भी जानती है कि देश की आर्थिक अजर सामजिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन चुकी हिन्दू राष्ट्रवाद और कथित विकसित भारत के सपने को संजोयी जनता वह सब स्वीकार करती जा रही है जो मोदी और बीजेपी के लोग कहते जा रहे हैं। अब हालिया इस रिपोर्ट में जो बाते सामने आयी है वह तो मोदी सरकार के तमाम दावे की धज्जियाँ उड़ा रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉप 10% लोग देश की 57.7% कमाई कंट्रोल करते हैं जबकि बॉटम 50% की कमाई का हिस्सा 22.2% से घटकर 15% हो गया है। रिपोर्ट कहती है कि अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद नहीं बढ़ रही। यानी जो पहले से पैसे वाले हैं, वो ज्यादा कमाई कर रहे हैं, लेकिन नए लोग इस ग्रुप में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल खर्च करना शुरू किया है। इन्हें 'उभरते हुए' या 'इच्छुक' ग्राहक कहा जा रहा है लेकिन ये लोग भी अपने खर्च को लेकर बहुत सावधान हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हाल के दिनों में लोगों की खर्च करने की ताकत कम हुई है, उनकी बचत भी तेजी से घट रही है और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस वजह से बाजार का तरीका बदल गया है और कंपनियां अब सस्ते सामानों की जगह प्रीमियम प्रॉडक्ट्स पर फोकस कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रियल एस्टेट सेक्टर है, क्योंकि इसमें ये ट्रेंड साफतौर पर नजर आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 5 साल पहले रियल एस्टेट की कुल बिक्री में अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी 40% थी, जो अब घटकर महज 18% रह गई है। ऐसे में देश के जो हालात है उसमे इंडिया के भीतर तीन इंडिया बनते गए हैं।

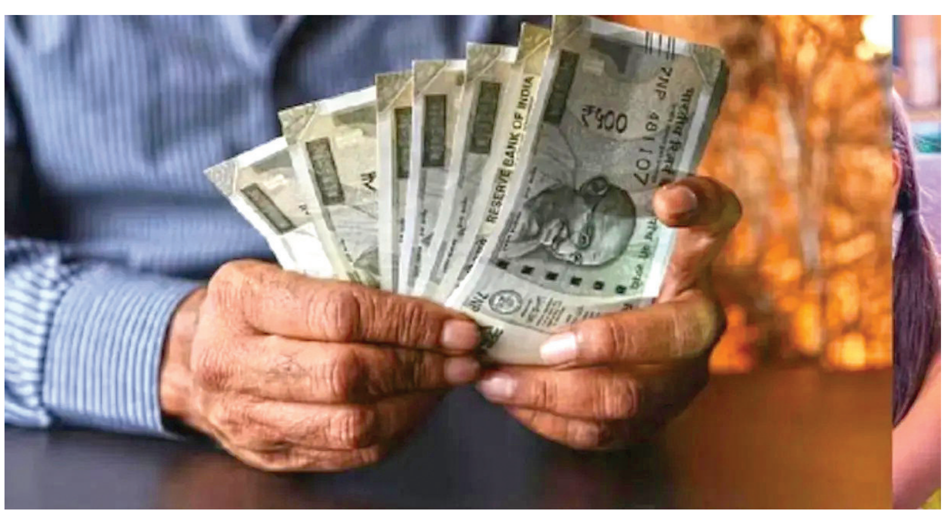

इंडिया के अंदर तीन इंडिया

इंडस वल्ली रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है. लेकिन इनमें से 100 करोड़ यानी लगभग दो तिहाई लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। मसलन, एक ही भारत में लगभग तीन भारत हैं. इनमें से एक हिस्सा सिर्फ़ 10% यानी लगभग 14 करोड़ लोगों का है। भारत के कुल खर्च का लगभग दो-तिहाई हिस्सा इसी वर्ग के हिस्से आता है। दूसरे हिस्से में लगभग 30 करोड़ लोग यानी 20 परसेंट जनसंख्या आती है। ये लगभग एक-तिहाई खर्च करते हैं. यानी बाक़ी जो 100 करोड़ लोग हैं, उनके पास खर्च करने को कुछ नहीं है। इस रिपोर्ट में भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास बताई गई है। इंडस वैली रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद मुख्य रूप से उपभोक्ता खर्च पर निर्भर है।

पहले वाले हिस्से को हम इंडिया वन मानकर चलते हैं। जिसमें सिर्फ़ 10% यानी लगभग 14 करोड़ लोग आते हैं. ये हिस्सा देश में दो-तिहाई या 66% खर्च के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट बताती है कि ये वर्ग सिर्फ़ 'गहरा' हो रहा है, 'व्यापक' नहीं। यानी इन लोगों की संपत्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन इस वर्ग में और लोग नहीं जुड़ रहे हैं। इनके पास मौजूद पैसों का बाक़ी के वर्गों में बंटवारा नहीं हो रहा है। यानी सबसे अमीर वर्ग, और भी ज़्यादा अमीर हो रहा है। इस वर्ग की प्रति व्यक्ति आय 15 हज़ार डॉलर यानी क़रीब 13 लाख रुपये बताई गई है। इस बात की पुष्टि ऐसे भी होती है कि हवाई यात्रा, दोपहिया वाहनों की ख़रीद, ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये वर्ग पॉश इलाक़ों में ही रहना पसंद करता है, जहां सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरह की चूक ना हो। अगर सिर्फ़ इसी वर्ग को भारत मानकर चला जाए, तो भारत एक विकसित देश बनने से पहले ही, एक एडवांस्ड इकॉनमी बन जाएगा। वहीं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया में 63वें स्थान पर होगा, जो कि अभी के 140वें स्थान से बहुत बेहतर है।

इंडिया टू में 20% यानी लगभग 30 करोड़ लोग आते हैं। इन लोगों को 'उभरते' या 'आकांक्षी' कंज्यूमर कैटगरी में रखा गया है। इन व्यक्तियों ने हाल में ज़्यादा खर्च करना शुरू किया है। लेकिन वो अपने खर्चों को लेकर सतर्क रहते हैं। इनकी प्रति व्यक्ति आय 3 हज़ार डॉलर यानी लगभग 2.5 लाख रुपये है। इसके बाद आता है तीसरा वर्ग, जिसमें 100 करोड़ लोग शामिल हैं। यानी भारत की आबादी का लगभग दो तिहाई भाग। इन लोगों के पास खर्च करने के पैसे ही नहीं हैं। इनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग एक हज़ार डॉलर यानी लगभग 85 हज़ार रुपये। इनके पास उतने ही पैसे होते हैं, जितने अफ़्रीका के ग़रीब देशों के लोगों के पास। रिपोर्ट कहती है कि जब तक इंडिया 2 और इंडिया 3 की आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक वो खर्च नहीं करेगी। खर्च नहीं होने पर हम इसी इंडिया वन पर निर्भर रहेंगे। भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ये सही है. लेकिन सही ये भी है कि प्रति व्यक्ति आय में हमारा रैंक 149 वां है। बता दें, अमेरिका, जर्मनी, जापान और चीन के बाद भारत दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा कंजंप्शन मार्केट है। बीते दस सालों में भारत के कंजंप्शन में बढ़ोतरी, इन अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा रही है। लेकिन जब बात प्रति व्यक्ति कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर आती है, तो भारत, चीन तो क्या, इंडोनेशिया से भी बहुत पीछे है। ये बताता है कि भारत में आर्थिक असमानता की खाई चौड़ी होती जा रही है।

उधर, माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में भी हालात ठीक नहीं हैं. दिसंबर 2024 तक इस सेक्टर के नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है और कुल लोन का 13% है। एनपीए का मतलब है वो लोन जो लोग वापस नहीं कर पा रहे। गरीब लोग माइक्रो फाइनेंस से छोटे-छोटे लोन लेते हैं, क्योंकि उन्हें बैंक से आसानी से लोन नहीं मिलता। लेकिन अब उनकी लोन चुकाने की ताकत कम हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक 91 से 180 दिन का बकाया लोन कुल आउटस्टैंडिंग का 3.3 फीसदी है, जबकि 180 दिन से ज्यादा बकाया लोन 9.7% है।

मणिपुर हिंसा से बेपटरी हुई जिंदगी

न्यूज़ डेस्क

दो साल से हिंसा की चपेट से बेहाल मणिपूर आज भी उसी राह पर है। वहां जातीय हिंसा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार पिछले दो साल से कहती रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन ठीक कुछ भी नहीं हुआ। कभी हिंसा की घटना थम जाती है तो कभी उग्र हो जाती है। जब हिंसा होती है तो लोगों की जाने जाती है ,आज भी वहां यही सब होता दिख रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रदेश से भागकर पड़ोसी राज्यों में शरण लेने को मजबूर हैं। महिलाओं और बच्चों की हालत सबसे ज्यादा ख़राब है। साल 2023 में मैतेयी और कुकी समुदायों के बीच लंबे समय से पल रहा मतभेद हिंसा की शक्ल में सामने आया था। इसके बाद से अब तक जारी हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 50 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं। जानकार जो आंकड़े बताते हैं उसके मुताबिक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और लाख से ऊपर लोग विस्थापन के शिकार हैं। बहुसंख्यक मैतेयी, मुख्य रूप से राज्य की इंफाल घाटी में बसे हुए हैं,जबकि कुकी लोगों की बसावट पहाड़ी इलाकों में है।

बता दें कि यह हिंसा मैतेयी लोगों की ओर से जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग किए जाने के बाद भड़की थी, जिससे नौकरियों में कोटा और जमीन के अधिकार जैसे विशेषाधिकार जुड़े होते हैं। कुकी लोगों को डर है कि अगर मैतेयी लोगों को जनजातीय दर्जा मिल जाता है तो वे और भी ज्यादा हाशिए पर चले जाएंगे।

भारत की केंद्र सरकार ने राज्य को दो विशेष जातीय जोन में बांट दिया है, जिसे एक बफर जोन अलग करता है। इस इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल की टुकड़ियां गश्त करती रहती हैं। इस कदम के बाद हिंसा में कमी तो आई है लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। मणिपुर में सरकार को लगातार मिलती नाकामी की एक मिसाल ये है कि केंद्र सरकार की ओर से हाईवे पर सामान्य यातायात बहाल करने की पहल को रोक दिया गया है। एक कुकी काउंसिल ने कहा है कि वो अपने इलाकों में सामान और लोगों के सामान्य यातायात का विरोध करते हैं। गौरतलब है कि मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण राज्य में हिंसा भड़क गई थी। यह दो साल पहले की बात है। दरअसल मैतेयी संगठनों ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग की थी. हाईकोर्ट में मैतेयी संगठनों ने एक याचिका दायर की थी। उस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने 19 अप्रैल को राज्य सरकार से इस मांग पर विचार करने और चार महीने के भीतर केंद्र को अपनी सिफारिश भेजने का निर्देश दिया था।

गैर-आदिवासी मैतेयी समुदाय लंबे अरसे से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। मैतेयी समुदाय की दलील है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद वे लोग राज्य के पर्वतीय इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे। आदिवासी संगठनों को चिंता है कि अगर मैतेयी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया तो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों से आदिवासियों को वंचित होना पड़ेगा।

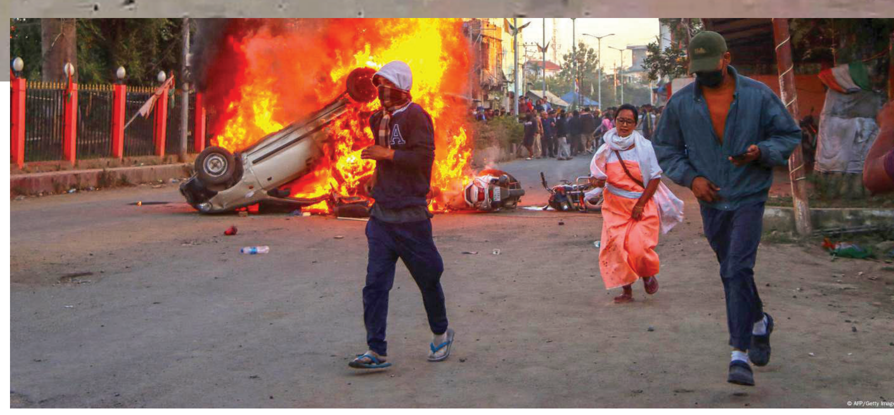

राज्य में हिंसा के फौरन बाद वहां सेना की तैनाती कर दी गई थी और तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए थे। हिंसा से निपटने के लिए सेना और असम राइफल्स के 10 हजार सैनिकों को तैनात किया गया है। हिंसाग्रस्त इलाकों में शांति बहाली के लिए सेना फ्लैग मार्च कर रही है।

हिंसा के बाद सेना ने कई हजार लोगों को कैंपों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया और उनके रहने का इंतजाम किया। करीब 23 हजार लोगों को सेना ने अपने कैंपों में रखा है। हिंसा के बाद से ही कई लोग राज्य छोड़कर चले गए हैं। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो पढ़ाई के लिए मणिपुर में थे। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम आदि के राज्यों ने अपने छात्रों को निकालने का इंतजाम किया है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने छात्रों को वहां से निकालने का फैसला किया है। मणिपुर की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मणिपुर में हिंसा की जांच एसआईटी से कराए जाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है।

फरवरी में, भारत सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। हालांकि राज्य के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ऐसा बीरेन सिंह के इस जातीय हिंसा का हल करने में असफल रहने के बाद किया गया था। साथ ही कुकी समूहों की ओर से उनपर यह आरोप भी लगाया गया था कि वो मैतेयी लोगों का पक्ष लेते हैं।

फरवरी में मणिपुर का शासन सीधे अपने हाथों में लेने के बाद केंद्र सरकार की ओर से राज्य में शांति का वादा किया गया था लेकिन वो भी नाकाम रहा। हालांकि हिंसा में काफी कमी आई है लेकिन जानकारों का यही कहना है कि लंबी शांति के लिए ऐसे मध्यस्थों की जरूरत है, जो तटस्थ हों और मैतेयी और कुकी दोनों ही समुदायों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर बातचीत कर सकें। इनके अलावा नागा समुदाय को भी इस बातचीत में शामिल किया जाए, जो राज्य के पहाड़ी हिस्सों में बसे हुए हैं।

वोटर कार्ड को आधार से लिंक करेगी सरकार

न्यूज़ डेस्क

केंद्र सरकार वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें दोनों को लिंक करने पर सहमति बनी। अब जल्द ही इस पर एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इससे पहले 2015 में भी ऐसी ही कोशिश हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया था।

चुनाव आयोग ने कहा, 'संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, लेकिन आधार केवल व्यक्ति की पहचान है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए सभी कानूनों का पालन किया जाएगा।' चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव, एमईआईटीवाई सचिव और यूआईडीएआई के सीईओ के साथ वोटर कार्ड-आधार सीडिंग के मुद्दे पर बैठक की। कानून मतदाता सूचियों को आधार डेटाबेस के साथ स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति देता है। सरकार ने संसद में बताया है कि आधार-वोटर कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। प्रस्तावित लिंकिंग के लिए कोई लक्ष्य या समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग अपने आधार कार्ड को मतदाता सूची से नहीं जोड़ते हैं, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे।

भारतीय निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार, वोटर-आधार को लिंक करने का मकसद आगामी चुनावों से पहले चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, समावेशिता और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। चुनाव आयोग 31 मार्च से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों और मुख्य चुनाव अधिकारियों के लेवल पर मीटिंग करेगा।इसके लिए पिछले 10 साल में पहली बार चुनाव आयोग ने कानूनी ढांचे के भीतर सभी राष्ट्रीय और राज्य-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक आधिकारिक तौर पर सुझाव मांगे हैं।

बता दें कि वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रयास चुनाव आयोग पहले भी कर चुका है। 2015 में चुनाव आयोग ने मार्च 2015 से अगस्त 2015 तक राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्यक्रम चलाया था। उस समय चुनाव आयोग ने 30 करोड़ से ज्यादा वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रोसेस पूरा कर लिया था। ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रुकी। दरअसल, वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 55 लाख लोगों के नाम वोटर डेटाबेस से हट गए थे। इसी को लेकर आधार की संवैधानिकता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को वोटर आईडी और आधार को लिंक करने से रोक दिया था। 26 सितंबर 2018 को आधार को लेकर दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के अलावा आधार को किसी भी सेवा के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है।

न्यू देहली पोस्ट

लोकपाल और हाईकोर्ट की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट का दखल

न्यूज़ डेस्क

सुप्रीम कोर्ट अब उस मामले की जांच करेगा जिसको लेकर लोकपाल और हाईकोर्ट के जजों के अधिकार को लेकर खींचतान चल रही है। लोकपाल का कहना है कि हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को वह देख सकता है जबकि हाईकोर्ट के जज ऐसा नहीं मानते। अब इसको लेकर शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह इस मसले की जांच करके ही अंतिम फैसला करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने में भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे की जांच करेगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई, सूर्यकांत और अभय एस ओका की तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ इस मुद्दे पर लोकपाल के 27 जनवरी के आदेश पर शुरू की गई स्वप्रेरणा कार्यवाही पर विचार कर रही थी।सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल तय करते हुए पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से मामले में न्याय मित्र के रूप में सहायता करने को कहा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीमित मुद्दा यह है कि क्या लोकपाल के पास अधिकार क्षेत्र है।

न्यायमूर्ती गवई ने कहा, "हम केवल लोकपाल अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र के संबंध में मुद्दे पर विचार करेंगे।" शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को लोकपाल के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि यह "बहुत ही परेशान करने वाला" है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके बाद इसने नोटिस जारी किए और केंद्र, लोकपाल रजिस्ट्रार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा। मेहता ने पहले कहा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कभी भी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं आएंगे। लोकपाल ने उच्च न्यायालय के एक मौजूदा अतिरिक्त न्यायाधीश के खिलाफ दायर दो शिकायतों पर आदेश पारित किया था। मंगलवार को शिकायतकर्ता शीर्ष अदालत के समक्ष पेश हुए और कहा कि उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में एक हलफनामा दायर किया है। उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि लोकपाल और न्यायपालिका का सम्मान बढ़े।"

पीठ ने शिकायतकर्ता से पूछा कि क्या वह कानूनी सहायता वकील नियुक्त करेंगे। शिकायतकर्ता ने किसी भी कानूनी सहायता से इनकार कर दिया और कहा कि हलफनामे में उनकी दलीलों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। मामले में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर इशारा करते हुए मेहता ने कहा, "मेरे विचार से, लोकपाल अधिनियम की केवल एक धारा की जांच की जानी है।" जब पीठ ने कहा कि लोकपाल के रजिस्ट्रार द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है, तो मेहता ने कहा कि यह लगभग "आदेश की पुनरावृत्ति" है। पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए पहले से ही एक तंत्र मौजूद है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो अदालत की सहायता भी कर रहे हैं, ने कहा, "मूल मुद्दा यह होगा कि क्या संवैधानिक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर कभी भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।"

पीठ ने कहा कि कुमार मामले पर निर्णय लेने से पहले शिकायतकर्ता के प्रस्तुतीकरण और अन्य सामग्रियों को समग्र दृष्टिकोण से देखेंगे। मेहता, जिन्होंने अपने लिखित प्रस्तुतीकरण दाखिल किए, ने तर्क दिया कि किसी भी उच्च न्यायालय को संसद के अधिनियम द्वारा "स्थापित" नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भारत के संविधान ने अनिवार्य संवैधानिक योजना के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय को जन्म दिया है। इसलिए, सॉलिसिटर जनरल ने लोकपाल के आदेश को रद्द करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सभी उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत स्थापित संवैधानिक न्यायालयों के रूप में माना जाना चाहिए। मेहता ने कहा कि यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संवैधानिक पद का धारक होता है और उसे सरकार का "कर्मचारी" नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, "भारत के लोकपाल ने विवादित आदेश में यह भी गलत माना है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 2013 अधिनियम की धारा 14(1) के खंड (एफ) में 'किसी भी व्यक्ति' की अभिव्यक्ति के दायरे में आएगा।"

सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए मेहता ने कहा कि यह माना गया था कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश एक विशिष्ट पद पर होता है और संवैधानिक पद पर होता है। लोकपाल आदेश में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी, न कि संसद के अधिनियम के तहत। मेहता ने कहा, "उच्च न्यायालयों के मामले में भी यही समानता लागू होनी चाहिए, न केवल अनुच्छेद 214 के कारण, बल्कि उच्च न्यायालय के संबंध में संविधान के अन्य प्रावधानों के कारण भी, जो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान के समान हैं।" उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 2013 अधिनियम के दायरे में नहीं आ सकता।

अपने आदेश में, लोकपाल ने दोनों मामलों में अपनी रजिस्ट्री में प्राप्त शिकायतों और प्रासंगिक सामग्रियों को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को उनके विचार के लिए भेजने का निर्देश दिया। आरोपों की योग्यता की जांच किए बिना, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली लोकपाल पीठ ने इस सवाल पर सकारात्मक रूप से विचार किया कि क्या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 2013 लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 के दायरे में आते हैं। आदेश में आगे कहा गया कि यह तर्क देना "बहुत भोलापन" होगा कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 2013 अधिनियम की धारा 14 (1) के खंड (एफ) में "किसी भी व्यक्ति" की अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आएगा।

आरोपों की योग्यता की जांच किए बिना, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली लोकपाल पीठ ने इस सवाल पर सकारात्मक रूप से विचार किया कि क्या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश २०१३ लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 के दायरे में आते हैं। आदेश में आगे कहा गया कि यह तर्क देना "बहुत भोलापन" होगा कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश २०१३ अधिनियम की धारा 14 (1) के खंड (एफ) में "किसी भी व्यक्ति" की अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आएगा।

गुजरात अधिवेशन में होगा कांग्रेस का पुनर्गठन सचिन और खेड़ा को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

राजनीतिक डेस्क

अधिकतर राज्यों में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस इस बार गुजरात में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में जुटी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक़ कांग्रेस भविष्य का रोडमैप तैयार करेगी और कुछ युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी देगी। वैसे राहुल गाँधी हर राज्यों में बड़े स्तर पर युवा नेताओं को पार्टी से जोड़ रहे हैं और उन्हें जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। लेकिन गुजरात में होने जा रहे अधिवेशन में कई बड़े अहम् फैसले होंगे। आगे बढे इससे पहले गुजरात अधिवेशन के बारे में कुछ जानकारी जरुरी है। जानकारी के मुताबिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) का राष्ट्रीय अधिवेशन 9 अप्रेल को अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर रिवरफ्रंट पर आयोजित होगा। गुजरात की धरती पर 64 साल बाद होने जा रहे इस अधिवेशन में देशभर से पार्टी के 3000 से अधिक नेता भाग लेंगे। इससे पहले 8 अप्रेल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शहर के शाहीबाग स्थित सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन में आयोजित होगी।

गुजरात प्रदेश कांग्रेस की ओर से इन दोनों ही प्रमुख कार्यक्रमों के लिए स्थलों को चुन लिया गया है।गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बताया कि सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक भवन में 8 अप्रेल सुबह 11.30 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी।इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के अलावा देश के कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व अन्य नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य व अन्य आमंत्रितों समेत 2000 से अधिक नेता भाग लेंगे। इसी दिन शाम को पांच बजे सभी नेतागण गांधी आश्रम पहुंचेंगे, जहां भजन संध्या व प्रार्थना सभा में हिस्सा लेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।9 अप्रेल को ऐतिहासिक साबरमती नदी के तट पर रिवरफ्रंट पर पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें देशभर से 3000 से अधिक नेता मौजूद रहेंगे। इस अधिवेशन की मेजबानी गुजरात कांग्रेस की ओर से की जा रही है। इससे पहले 1961 में भावनगर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का गुजरात में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन सूरत के हरीपुरा में 1938 में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में सुभाषचंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। हरिपुरा अधिवेशन की पूरी जिम्मेदारी सरदार पटेल ने निभाई थी। राज्य में पार्टी का यह तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन होगा।

गोहिल ने बताया कि 100 वर्ष पूर्व 1925 में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सरदार वल्लभभाई पटेल गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। वे लगातार 25 वर्ष तक अध्यक्ष रहे थे। पटेल की जयंती के 150 वर्ष तथा पुण्यतिथि के 75 वर्ष पूरे होने के चलते पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सरदार पटेल स्मारक शाहीबाग में और राष्ट्रीय अधिवेशन साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित करने का निर्णय किया है। राहुल गाँधी अभी बिहार और यूपी को साध रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट के बारे में कई तरह की बातें की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट के बारे में पार्टी के भीतर दो तरह की बात चल रही है। पहली बात तो यह है कि उन्हें राजस्थान तक ही सीमित रखा जाए और उन्हें प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन पार्टी के भीतर की नेता यह भी चाहते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी जाए। सूत्रों के मुताबिक सचिन को पार्टी संगठन करने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अभी पार्टी संगठन की जिम्मेदारी वेणुगोपाल के ऊपर है लेकिन पार्टी चाह रही है कि वेणुगोपाल की जगह अब सचिन को लाया जाये। संभव है कि गुजरात अधिवेशन में इस पर निर्णय हो सकता है। सचिन पार्टी के बेहतरीन नेता हैं और युवाओं में उनकी ख़ास पहचान भी है। राहुल गाँधी भी चाहते हैं कि सचिन को अब बड़ी जिम्मेदारी देने का समय आ गया है। ऐसे में गुजरात अधिवेशन में सचिन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है।

इधर पवन खेड़ा को लेकर भी पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। जयराम रमेश अभी पार्टी के संचार विभाग को देख रहे हैं और सत्ता पक्ष पर हमला भी करते रहे हैं। लेकिन राहुल गाँधी अब चाहते हैं कि जीरम रमेश को भी दक्षिण के रज्यों में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाये। ऐसे में पवन खेड़ा के पास संचार विभाग की बड़ी जिम्मेदारी जा सकती है। पवन खेड़ा को रज्य सभा में भेजने की बायत भी हो रही है। पार्टी चाहती है कि बिहार और अगले साल होने वाले कई रज्यों में चुनाव से पहले पवन खेड़ा और सचिन पायलट को बड़े मिशन पर लगा दिया जाये। ऐसे में गुजरात अधिवेशन में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस को मिली चुनावी हार के बाद पार्टी में फिर से जान फूंकने के लिए कमर कस चुके हैं। राहुल 27, 28 मार्च और 3 अप्रैल को देशभर के 750 से अधिक जिला इकाई प्रमुखों से सीधे कांग्रेस की जमीनी हकीकत जानेंगे। राहुल गांधी जिला इकाई प्रमुखों की फीडबैक का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को फिर से पटरी पर लाने में इस्तेमाल करेंगे। करीब 250 के बैच में होने वाले इस संवाद से पहले अलग-अलग राज्य इकाइयां जिला स्तर पर रिक्त पदों को सक्रिय रूप से भरने में जुटी हैं।

तीन दिवसीय संवाद के दौरान, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष स्थानीय टीम प्रमुखों से महत्वपूर्ण फीडबैक प्राप्त करेंगे। साथ ही उन्हें उस पुरानी पार्टी में उनके नए महत्व का आश्वासन देंगे, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में खुद को पुनर्जीवित करने के लिए इच्छुक है। गांधी परिवार के गृह राज्य उत्तर प्रदेश में, पार्टी ने हाल ही में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सभी राज्य टीमों को भंग करने के महीनों बाद सभी 75 जिलों में जिला इकाई प्रमुखों की नियुक्ति की है। उत्तर प्रदेश में संगठन लंबे समय से पार्टी प्रबंधकों के लिए एक समस्या रहा है, जहां कांग्रेस के पास 403 विधायकों में से केवल 2 और 80 सांसदों में से मात्र 6 हैं। राहुल उन छह सांसदों में से एक हैं और भाजपा शासित राज्य में खोई जमीन को बरकरार रखने के लिए पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं में जोश भरते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि, राहुल गांधी संगठनात्मक पुनर्गठन की देखरेख कर रहे हैं। लेकिन पार्टी की नजर सबसे ज्यादा सचिन पायलट ,पवन खेड़ा और जयराम रहेश के लिए बड़ी जिम्मेदारी देने पर है।

गांधी परिवार के गृह राज्य उत्तर प्रदेश में, पार्टी ने हाल ही में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सभी राज्य टीमों को भंग करने के महीनों बाद सभी 75 जिलों में जिला इकाई प्रमुखों की नियुक्ति की है।

बिहार में कांग्रेस की 'नौकरी दो,पलायन रोको' यात्रा का राजनीतिक सच

राजनीतिक डेस्क

क्या आपने कभी पंजाब या हरियाणा के लोगों को हमारे खेतों में काम करते देखा है?" "हमारे पास कोई बेंगलुरु या हैदराबाद क्यों नहीं है? यह सच्चाई बिहार का सबसे बड़ा दंश है।'' ये शब्द हैं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के जिन्होंने बीते रविवार से बिहार की यात्रा शुरू की है। जाहिर है कांग्रेस की यह यात्रा ठीक बिहार चुनाव से पहले की जा रही है। इस यात्रा का मकसद यही है कि बिहार कांग्रेस से बिहारी समाज और युवाओं को जोड़ा जाए ताकि संगठन भी मजबूत हो और चुनाव में बेहतर परिणाम भी मिले। रविवार को कांग्रेस की यह यात्रा चम्पारण के भितिहरवा से शुरू की गई। वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने 1917 में अपना प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। खबर के मुताबिक़ यह यात्रा लगभग एक महीने तक चलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस यात्रा के जो नारे हैं -''पलायन रोको ,नौकरी दो '' बिहार समाज और युवाओं को कितना आकर्षित कर पाते हैं इस पर देश की नजर लगी हुई है।

कन्हैया के सवाल पर सभी ने तालियाँ बजाकर जवाब दिया: "हमारे पास कोई बेंगलुरु या हैदराबाद क्यों है? कन्हैया ने आगे कहा कि पलायन के मुद्दे को जानबूझकर राजनीति और चुनावों से दूर रखा गया है। हम यह यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि युवाओं से जुड़े मुद्दे चुनाव घोषणापत्र में शीर्ष पर हों। कन्हैया ने कहा, "हम पलायन का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी को रोजगार मिले। पलायन शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और काम के अवसरों की कमी के कारण होता है। स्थिति ऐसी है कि बिहार के लोगों को न केवल नौकरी के लिए बल्कि अपने हनीमून के लिए भी बाहर जाना पड़ता है।"

कन्हैया ने आगे कहा कि अगर हम बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों और युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना होगा और उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। यात्रा की शुरुआत करते हुए बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि बिहार की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो रही है, जिसमें परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने या भर्ती में देरी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जैसे मुद्दे शामिल हैं। अल्लावरु ने कहा, "कोई भी महंगाई के बारे में बात नहीं करता है जो आम लोगों की जेब और बचत को खा जाती है। कोई भी शिक्षा की समस्याओं का जिक्र नहीं करता है, जिसके कारण हमारे बच्चे राज्य छोड़कर चले जाते हैं। अच्छे और सस्ते अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी एक समस्या है, जिसके कारण लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है।"

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी ने कहा कि बिहार के लोगों की पीड़ा को देखते हुए कांग्रेस उनकी आवाज बनने जा रही है और सरकार से सवाल करेगी। अल्लावरु ने कहा, "यह यात्रा बिहार के युवाओं के अधिकारों और रोजगार की लड़ाई है। यह यहां 'न्याय क्रांति' की शुरुआत है। यह राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाएगी।" यह पदयात्रा 24 दिनों में तीन चरणों में पूरे राज्य में घूमेगी और 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर पटना में समाप्त होगी। यह पहले चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों से गुजरेगी।

पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग आठ महीने बाकी हैं। यह यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर द्वारा हाल ही में की गई यात्राओं के बाद हो रही है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरना और पार्टी को पुनर्जीवित करना है, जो पिछले कुछ सालों में कमजोर हो गई है और जिसे राजद के अधीनस्थ सहयोगी के रूप में देखा जाता है। ऐसे प्रासंगिक मुद्दे उठाए जाएंगे जो लोगों के दिल को छू सकें और उनका समर्थन हासिल कर सकें। लेकिन इस यात्रा के कई अजर भी मायने हैं। बिहार में कांग्रेस फिर से की तैयारी में हैं। अब वह पिछली पंक्ति की पार्टी बन कर रहना नहीं चाहती। 90 की दशक के बाद से ही कांग्रेस बिहार में कमजोर होती गई और उसके वोट बैंक राजद ,जदयू और बीजेपी के साथ होते चले गए। बाद में तो कांग्रेस की हालत यह हो गई कि वह राजद नेता लालू यादव के इशारे पर चलने लगी। लगभग अब भी वही हाल है। लेकिन अब कांग्रेस न केवल राजद के चंगुल से बाहर निकलने को तैयार है बल्कि वह अपने पैरों पर भी खड़ा होने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को इस मामले में कितनी सफलता मिलती है यह तो देखने की बात होगी लेकिन जिस तरह से कन्हैया और पप्पू यादव के जरिये कांग्रेस बिहारी युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है उससे बिहार में हलचल तो मच ही गई है। बिहार के दलित ,पिछड़े और मुसलमान अब कांग्रेस को नए सिरे से देखने लगे हैं लेकिन यह भी समाजखने की बात होगी कि कांग्रेस अगर आगे बढ़ती है तो राजद के साथ उसके सम्बन्ध कैसे होंगे ? फिर राजद नेता तेजस्वी यादव की अगली राजनीति पर कांग्रेस के बढ़ते कदम का क्या असर पडेगा ? फिर चुनाव के दौरान महागठबंधन किस करवट लेगा यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस के कदम अब पीछे हटने वाले नहीं है।

जहरीला भूजल की चपेट में बिहार के 30 हजार से ज्यादा ग्रामीण वार्ड

न्यूज़ डेस्क

हाल ही में जारी किया एक सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार के 38 जिलों में से 31 जिलों के करीब 30207 ग्रामीण वार्ड जहरीले भूजल के प्रकोप में है और इससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। हाल ही में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2024-25) के हिस्से के रूप में विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में 4,709 ऐसे वार्डों में भूजल में आर्सेनिक, 3,789 वार्डों में फ्लोराइड और 21,709 वार्डों में आयरन की मौजूदगी पर प्रकाश डाला गया है। ये प्रभावित वार्ड बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, लखीसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर, सीतामढी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई, बांका, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और किशनगंज जिलों में स्थित हैं। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया, "हम इस तथ्य से अवगत हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, राज्य सरकार ने ग्रामीण बिहार को 'हैंडपंप-मुक्त' बनाने और 'हर घर नल का जल' योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।"उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहु-ग्राम योजनाएं (एमवीएस) भी लागू कर रही है।

मंत्री ने कहा कि 'हर घर नल का जल' योजना के तहत पीएचईडी ग्रामीण क्षेत्रों में 83.76 लाख परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा रहा है। साथ ही, 30,207 ग्रामीण वार्डों में परिवारों को पीने योग्य पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां प्रदूषण अधिक है। मंत्री ने कहा, "राज्य सरकार पहले से ही नदी के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रही है। सितंबर 2024 में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम शहरों में आवश्यक उपचार के बाद पीने के लिए सोन नदी से पानी की आपूर्ति के लिए 1,347 करोड़ रुपये की परियोजना की आधारशिला रखी थी।" उन्होंने कहा कि इस योजना में सोन नदी के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इन शहरों की भूजल पर निर्भरता खत्म हो जाएगी।यह परियोजना दो साल में पूरी होने की संभावना है। बता दें कि 2023 में, सीएम ने गया, राजगीर और नवादा के लोगों को महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना या 'गंगा जल पूर्ति योजना' समर्पित की थी और इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है लेकिन जहरीले पानी से लोगों का बचाव करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती आज भी है।

बिहार के एक प्रमुख गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. मनोज कुमार ने बताया, "भूजल में रासायनिक संदूषण का उच्च स्तर निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अधिकारियों को संदूषण के स्रोत की पहचान करनी चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा, दूषित भूजल के सेवन के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभावित वार्डों में नियमित आधार पर शिविर भी आयोजित किए जाने चाहिए। अधिकारियों को पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता का मानकीकरण और वर्गीकरण करना चाहिए। कुमार ने कहा कि "पानी में कई हानिकारक घटक हो सकते हैं, फिर भी देश में पीने के पानी के लिए कोई मान्यता प्राप्त और स्वीकृत मानक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषक का प्रकार और उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव जल स्रोत के आधार पर अलग-अलग होते हैं।

बिहार में कांग्रेस का दलित दांव, अखिलेश आउट, राजेश राम इन

राजनीतिक डेस्क

आगामी बिहार विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की हैसियत कितनी मजबूत होती है और उसके साथ कितने जातीय वोट जुड़ पाते हैं यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने एक भूमिहार नेता को हटाकर एक दलित नेता राजेश राम को बिहार का मुखिया बनाया है उससे राजद के साथ ही बीजेपी के भीतर भी हड़कंप मच गया है। कांग्रेस का यह खेल अब महागठबंधन पर कितना असर डालेगा इस पर भी चर्चा की जाने लगी है। जाहिर है कि कांग्रेस के इस कदम से राजद प्रमुख लालू यादव भी परेशान हो गए हैं। उधर नीतीश कुमार को भी समझ में आ गया है कि इस बार कांग्रेस बिहार में कुछ बड़ा करने को तैयार है। और यह तैयारी कुछ वैसी ही है जैसा कि कांग्रेस ने दिल्ली में किया है। दिल्ली चुनाव में आप और बीजेपी के बीच लड़ाई थी लेकिन कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया कि आप बुरी तरह से हार गई। कुछ ऐसा ही खेल आप ने कांग्रेस के साथ हरियाणा और गुजरात में किया था और कांग्रेस की हार गई थी। राजद अजर जदयू अब जान गए हैं कि कांग्रेस को भले ही बिहार में सत्ता की बड़ी उम्मीद नहीं है लेकिन जो पार्टियां सत्ता के करीब खुद को देख रही है उसका खेल कांग्रेस इस बार ख़राब कर सकती है।

बिहार विधानसभा चुनाव के 7 माह पहले कांग्रेस आलाकमान ने कुटुम्बा के विधायक राजेश कुमार को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने अखिलेश सिंह की छुट्टी करते हुए संभवतः पहली बार किसी दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। राजनीतिक हलको में माना जा रहा है कि कांग्रेस ने दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लंबा गेम प्लान किया है। बिहार में चमार जाति की आबादी करीब साढ़े पांच फीसदी है। कुछ इतनी ही आबादी पासवान समाज की भी है जिसकी राजनीति चिराग पासवान करते रहे हैं। अभी तक चमार समाज का वोट बैंक राजद ,जदयू और बीजेपी के बीच बंटता रहा है जबकि बड़ी सच्चाई यही है कि यही चमार समाज के लोग कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे। लेकिन बाद के वर्षों में यह वोट बैंक कई पार्टियों बंटता रहा। अब राहुल गाँधी ने अपने पुराने वोट बैंक को साधने के लिए राजेश राम पर दांव लगाया है। कांग्रेस का यह दांव कितना सफल होगा यह देखने की बात होगी। राजेश कुमार के पिता स्व. दिलकेश्वर राम कांग्रेस में जगजीवन राम के बाद दलित समाज के सर्वमान्य नेता रहे है। उनके सरल और मृदुल व्यवहार का हर कोई कायल रहा है। वे पार्टी में हर वर्ग के नेताओं खासकर पूर्व मुख्यमंत्री स्व. सत्येंद्र नारायण सिन्हा के सर्वाधिक प्रिय रहे हैं। राजेश और उनके पिता का चेहरा और कार्यशैली भी एक समान है। इस वजह से पार्टी में भी राजेश की छवि को दिलकेश्वर राम जैसा ही देखा जा रहा है। वैसे भी कांग्रेस आलाकमान बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पुराने नेताओं के जगह पर नई पीढ़ी के उर्जावान नेताओं को प्रोमोट कर रही है। इसकी पहली झलक युवा तुर्क कन्हैया कुमार को प्रोमोट करने के लिए शुरु की गई रोजगार दो यात्रा में दिखी और यात्रा के शुरू होने के चंद दिन बाद ही पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान राजेश कुमार के हाथों में सौंप दी। जानकार बताते है कि राजेश कुमार और कन्हैया कुमार के बीच अच्छी ट्यूनिंग है। दोनों की अपनी जातीय समाज में भी अच्छी पकड़ है और दोनों की यह ट्यूनिंग दो बड़े वर्ग के वोटो को पार्टी से जोड़ने में सहायक हो सकती है।

सीएम नीतीश पुत्र निशांत कुमार क्या लड़ेंगे चुनाव?

राजनीतिक डेस्क

यह बात और है कि न तो निशांत कुमार और न ही सीएम नीतीश कुमार और जदयू ने कोई ऐसी बात कही है जिससे पता चले कि नीतीश पुत्र निशांत कुमार अबकी बार बिहार चुनाव में खड़े होंगे। लेकिन सड़कों से लेकर जदयू कार्यालय में निशांत कुमार को लेकर पोस्टरबाजी खूब हो रही है। जदयू के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि निशांत कुमार इस बार चुनाव लड़ेंगे। जदयू के लोगों ने इस बावत पोस्टर भी चस्पा किया है जिसपर लिखा हुआ है कि ,"बिहार की मांग, सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। " इसके बाद से ही बिहार में चर्चा तेज है कि निशांत इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि नीतीश कुमार हमेशा से ही वंशवादी राजनीति के खिलाफ रहे हैं। निशांत ने झारखंड के मेसरा में स्थित बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइस की पढ़ाई की है। पटना के कंकड़बाग में स्थित एक पार्क का नाम नीतीश की पत्नी मंजू सिन्हा के नाम पर रखा गया है। साल 2017 की फरवरी में इस पार्क में अपनी मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद निशांत ने कहा था,"मैं कभी भी राजनीति में प्रवेश नहीं करुंगा। मैंने आध्यात्म को स्वीकार कर लिया है। " उनके इस बयान ने उनके राजनीति में आने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया था.लेकिन पिछले कुछ समय से निशांत अपनी सार्वजनिक उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। हाल ही में वे नीतीश कुमार के साथ बख्तियारपुर स्थित अपने पैतृक घर गए थे। इस दौरान उन्होंने जनता से अपने पिता और जेडीयू का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे नीतीश कुमार को फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं।

खास बात यह है कि निशांत कुमार के राजनीति में आने या न आने को लेकर अभी तक न तो नीतीश कुमार ने कुछ कहा है और न ही जेडीयू ने। बिहार सरकार में मंत्री जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे,पार्टी उसे स्वीकार करेगी। उन्होंने कहा, "जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीतिक भविष्य की बात है, यह पार्टी नीतीश कुमार द्वारा स्थापित की गई है। वे ही इसके नेता हैं। इस पार्टी में उन्हीं का निर्णय अंतिम होता है। पार्टी का भविष्य उन्हीं के फैसले पर निर्भर है,जो भी वे तय करेंगे, पार्टी उसे स्वीकार करेगी। " वहीं जेडीयू के कुछ दूसरे वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि निशांत राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अन्य राजनीतिक परिवारों का उदाहरण देते हुए कहा कि 2014 में लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी का नेतृत्व अपने बेटे चिराग पासवान को सौंपा था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी निशांत के राजनीति में आने की संभावना का स्वागत किया है। न्होंने निशांत को योग्य और सक्षम बताते हुए कहा कि भारत में कई नेताओं के बच्चे और परिवार राजनीति में आए हैं। अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आना चाहते हैं, तो इसमें चर्चा की कोई जरूरत नहीं है.अगर वे राजनीति में आते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे।

न्यू देहली पोस्ट

बस्तर होगा 2026 तक नक्सल मुक्त!

न्यूज़ डेस्क

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ हो रही है और नक्सली बड़ी संख्या में मारे भी जा रहे हैं। पिछले कुछ महीने के भीतर ही बड़े पैमाने पर नक्सलियों को मार गिराया गया है और काफी संख्या में नक्सलियों ने सरकार के समक्ष समर्पण भी किया है। इधर बीजापुर और कांकेर में दो अलग-अलग मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने कुल 30 नक्सलियों मार गिराया है। इसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस संकल्प को दृढ़ कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का प्रण लिया गया है। हालांकि बीजापुर और कांकेर में सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड़ में देश ने एक जवान शहीद खो दिया है।

बीजापुर और कांकेर में सुरक्षाबलों के हाथों मारे गए नक्सलियों पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद के विरूद्ध लड़ाई जारी है। उन्होंने संकल्प दोहराते हुए कहा कि अगले साल मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है।

सीएम साय ने आगे लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी व माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्च 2026 तक देश-प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए, सुरक्षाबल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जवानों को मिली यह सफलता सराहनीय है। उनके साहस को नमन करता हूं।

बीजापुर और कांकेर के मुठभेड़ स्थल से सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षाबलों के हाथों मार गिरा गए 30 नक्सलियों को 'बड़ी सफलता' करार दिया है। और कहा कि मार्च 2026 से पहले देश नक्सल-मुक्त होने वाला है।

गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पर लिखा कि, नक्सल मुक्त भारत अभियान' की दिशा में आज हमारे जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। बीजापुर और कांकेर में सुरक्षाबलों के 2 अलग-अलग ऑपरेशन में 22 नक्सली मारे गए हैं।

सिंहस्थ 2028 के लिए मध्यप्रदेश में शुरू हुई बड़ी तैयारी

सीएम ने कहा कि सिंहस्थ २०२८ को अद्भुत और ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार अभी से कार्य कर रही है। उधर ,अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने साधु संतों से वादा किया है कि सिंहस्थ २०२८ का स्नान शिप्रा नदी के जल से ही होगा।

न्यूज़ डेस्क

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को अद्भुत और ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार अभी से कार्य कर रही है। सिंहस्थ 2028 के लिए 2000 करोड़ का बजट इसी साल जोड़ा गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सिंहस्थ 2028 में 25 करोड़ श्रद्धालु के उज्जैन आने की संभावना है, जिसे देखते हुए अभी से व्यवस्था की जा रही है।

सीएम ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को अद्भुत और ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार अभी से कार्य कर रही है। उधर ,अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने साधु संतों से वादा किया है कि सिंहस्थ 2028 का स्नान शिप्रा नदी के जल से ही होगा। शिप्रा नर्मदा लिंक योजना के बाद शिप्रा नदी में पर्व और त्योहारों के दौरान नर्मदा का जल भी प्रवाहित किया जाता है। शिप्रा नदी के जल से सिंहस्थ के अमृत स्नान को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सरकार सिंहस्थ को सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी।

बता दें कि सिंहस्थ भले ही साल 2028 में हो लेकिन सूबे की मोहन यादव सरकार अभी से इसकी तैयारियों में जुट गई है।

मोहन सरकार ने फिर लिया कर्ज ,जनता पर बढ़ी बोझ

न्यूज़ डेस्क

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने 6 हजार करोड़ रुपए का कर्ज फिर से लिया है । यह कर्ज 2000-2000 करोड़ की तीन किस्त में लिया गया है। इसे सरकार 7 साल, 21 साल और 24 साल में चुकाएगी। 12 मार्च को सरकार ने सदन में बजट पेश किया था । इसके सात दिन बाद कर्ज लिया गया है । चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने यह 11वीं बार यह कर्ज लिया है। सिर्फ मार्च में ही तीसरी बार कर्ज लिया गया है।

सरकारी रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो मार्च की शुरुआत में यानी पांच तारीख को 2000-2000 हजार करोड़ का कर्ज तीन अलग-अलग किस्तों में (14 साल, 20 साल और 23 साल के लिए) लिया गया। फिर 7 दिन बाद 12 मार्च को दो किस्तों में कर्ज लिया। अब 19 मार्च को फिर से तीन किस्तों में कर्ज लिया। राज्य का कर्ज बजट से ज्यादा हो गया है। 2026 में कर्ज 4.99 लाख करोड़ हो जाएगा, जबकि नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 4.21 लाख करोड़ का बजट पेश किया है।

कांग्रेस ने विरोधस्वरूप कर्ज पंचमी मनाई। वरिष्ठ नेता मनोज शुक्ला के नेतृत्व में भोपाल में कार्यकर्ताओं ने राहगीरों को गुलाल लगाकर कर्ज के बारे में जानकारी दी। आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए कर्ज ले रही है। इस दौरान कार्यकर्ता तख्तियां लिए थे। इनमें कर्ज के विरोध में स्लोगन लिखे थे। उनका कहना है कि सरकार कर्ज की रकम कहां ले जा रही है, इसका जवाब देना होगा।

यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल हुआ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

न्यूज़ डेस्क

छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपनी अनूठी जैव विविधता के साथ भारत का नया यूनेस्को धरोहर दावेदार बन गया है। इस उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि कांगेर घाटी की खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्त्व ने इसे इस मुकाम तक पहुंचाया है।

दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस स्थल को वैश्विक पहचान दिलाने की योजना बनाई थी। विशेषज्ञों ने इसकी जैव विविधता, पुरातात्विक धरोहर और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का गहराई से अध्ययन किया और फिर इसका नाम यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ का कोई स्थल इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुआ है। अब पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इसे स्थायी विश्व धरोहर का दर्जा भी मिल सकता है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सफलता को लेकर कहा है कि यह कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम है। साय ने कहा है, ''कांगेर घाटी का यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल होना राज्य के लिए गौरव का विषय है, जिससे पर्यटन एवं रोजगार में नई संभावनाएं खुलेंगी। हम भविष्य में भी अपनी धरोहरों के संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास करते रहेंगे।'

अधिकारियों ने बताया कि कांगेर घाटी सिर्फ जंगल नहीं है, यह एक जादुई दुनिया है। यहां 15 से ज्यादा रहस्यमयी गुफाएं हैं, जैसे कोटमसर, कैलाश और दंडक गुफाएं, जो किसी रहस्यलोक से कम नहीं लगतीं। उन्होंने बताया कि यहां 15 से अधिक चूना पत्थर की गुफाएं हैं। यहां की टमसर, कैलाश, दंडक गुफाएं न सिर्फ भूवैज्ञानिक चमत्कार हैं, बल्कि पुरातात्विक कहानियां भी समेटे हुए हैं। इस उद्यान में ऊदबिलाव, माउस डियर, जायंट गिलहरी, लेथिस सॉफ्टशेल कछुआ, जंगली भेड़िया जैसे दुर्लभ प्राणी भी निवास करते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि यहां पक्षियों की दो सौ से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं तथा नौ सौ से अधिक वनस्पतियां भी हैं। यहां तितलियों की 140 से अधिक प्रजातियां हैं। उन्होंने बताया कि यूनेस्को की अस्थायी सूची एक खास सूची होती है, जिसमें दुनिया के वह स्थान शामिल किए जाते हैं, जिन्हें भविष्य में विश्व धरोहर घोषित किया जा सकता है और यह पहला और सबसे अहम कदम होता है।

पंजाब में सरकार और किसान आमने - सामने

न्यूज़ डेस्क

पंजाब में सरकार और किसानों के बीच जारी खींचतान के बीच 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इन सब के बीच अब पंजाब सरकार ने किसान संगठनों के साथ एक अहम बैठक बुलाई है।

बैठक में किसान संगठनों और पंजाब सरकार के बीच वार्ता की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके और समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इस बैठक में एसकेएम पंजाब और भारतीय किसान यूनियन (उग्राहा जत्थेबंदी) के प्रमुख नेताओं को शामिल किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया करेंगे, जो किसानों के साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेंगे।

बैठक का आयोजन शुक्रवार शाम चार बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में किया जाएगा। इस बैठक के दौरान सरकार और किसान संगठनों के बीच कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा, जिसमें किसानों के अधिकारों और उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। एसकेएम द्वारा 26 मार्च को किए गए विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद यह बैठक और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यह किसानों और सरकार के बीच के विवादों को सुलझाने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि पंजाब पुलिस ने बुधवार को विभिन्न मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के टेंटों को ध्वस्त कर दिया था और धरने पर बैठे किसानों को हटा दिया था। इसके साथ ही प्रमुख किसान नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर को हिरासत में ले लिया गया। किसान नेता शंभू बॉर्डर की ओर जा रहे थे, लेकिन मोहाली में पंजाब पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

पंजाब पुलिस ने बुधवार को विभिन्न मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के टेंटों को ध्वस्त कर दिया था और धरने पर बैठे किसानों को हटा दिया था। इसके साथ ही प्रमुख किसान नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर को हिरासत में ले लिया गया। किसान नेता शंभू बॉर्डर की ओर जा रहे थे, लेकिन मोहाली में पंजाब पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

सरकार की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद तमाम किसानों ने कड़ा एतराज जताया है। इसी बीच एसकेएम ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा कि पंजाब सरकार के रास्ते का मामला है और वे इस मुद्दे पर किसानों के साथ बातचीत कर सकते थे। केंद्र सरकार चाहती है कि किसान और पंजाब सरकार के बीच टकराव बना रहे। हमारी यही मांग है कि किसानों को रिहा किया जाए। साथ ही पंजाब के सीएम को किसानों से बातचीत करनी चाहिए और समन्वय स्थापित करना चाहिए। हमारी मांगें केंद्र सरकार के पास हैं और पंजाब को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो पूरा आंदोलन पंजाब में चला जाएगा।

राजस्थान में कुलपति का नाम अब होगा कुलगुरु

प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कुलपति शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि यह संस्कृत साहित्य से जुड़ा शब्द है और इसका उपयोग प्राचीन ग्रंथों में भी हुआ है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा आज कुलपति शब्द अच्छा नहीं लग रहा आखिर कारण क्या है।

न्यूज़ डेस्क

राजस्थान विधानसभा में विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक पर जोरदार बहस के बाद इसे पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के तहत प्रदेश के 32 सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में कुलपति का पदनाम बदलकर 'कुलगुरु' और प्रतिकुलपति का नाम 'प्रतिकुलगुरु' कर दिया गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बाहरी कुलपतियों की अधिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की 32 विश्वविद्यालयों में से सिर्फ चार में ही राज्य के कुलपति हैं, जबकि सबसे ज्यादा कुलपति उत्तर प्रदेश से नियुक्त किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जूली ने एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का उदाहरण देते हुए बताया कि महाराष्ट्र से एक गैर-डॉक्टर को कुलपति नियुक्त कर दिया गया है, जो इस पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा और 4,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं।

प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कुलपति शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि यह संस्कृत साहित्य से जुड़ा शब्द है और इसका उपयोग प्राचीन ग्रंथों में भी हुआ है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा आज कुलपति शब्द अच्छा नहीं लग रहा आखिर कारण क्या है। बीजेपी सनातन धर्म की बात करती है, लेकिन यह नाम परिवर्तन पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं। कांग्रेस ने ही संस्कृत निदेशालय की नींव रखी थी, कुलपति का नाम तो बदल दिया, अब कुलाधिपति का क्या करेंगे। जूली ने सरकार की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिर्फ नाम बदलने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, जब तक कि विश्वविद्यालयों में वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म के संस्कार नहीं लाए जाएंगे। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति पैसों के आधार पर हो रही है। उन्होंने कहा, जो बड़ी अटैची देता है, उसे कुलपति बना दिया जाता है. इससे नई पीढ़ी का नुकसान हो रहा है।

क्यों पुलिस छावनी में तब्दील है जालंधर कैंट ?

न्यूज़ डेस्क

शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 माह से चल रहे किसानों के धरने को पंजाब सरकार ने बुधवार रात पुलिस की मदद से हटा दिया। बुलडोजर चलाकर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बने मंच ढहा दिए और टेंट भी उखाड़ दिए।

वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए गए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को इलाज के लिए जालंधर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (पिम्स) अस्पताल में लाया गया था। डल्लेवाल को रात दो बजे अस्पताल में भर्ती किया गया था। पुलिस के पूरे काफिले के साथ भारी सुरक्षा में किसान नेता को जालंधर लाया गया व उनका इलाज करवाया गया। अस्पताल के बाहर की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुलाजिम तैनात कर दिए गए थे और अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

इलाज के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को जालंधर कैंट स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है।जालंधर कैंट के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के गेट पर ही मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर हाईटेक एंबुलेंस तैनात कर दी गईं हैं। वहां भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इतनी सुरक्षा की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहां हर आने जाने वाले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस जवान वाहन चालकों के दस्तावेज चेक कर रहे हैं। निजी वाहनों में आने जाने वालों की भी चेकिंग की जा रही है।

शंभू बॉर्डर पर हाईवे को खोलने का काम जारी है। एसएसपी पटियाला शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और पुलिस पार्टी के साथ रोड क्लियर करवाने में जुटे हुए हैं। वहीं हरियाणा प्रशासन भी काफी तेजी से रास्ता खोलने में लगा है। एसडीएम राजपुरा का कहना है कि पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल तक एक तरफ का रास्ता खुल जाएगा।

सिरसा में रेलवे की बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव

न्यूज़ डेस्क

सिरसा में रेलवे की कई एकड़ जमीन पर कॉमर्शियल मार्केट बनने जा रही है। यहां रेलवे पटरी के साथ लंबे-चौड़े एरिया में पार्क भी विकसित किया जा चुका है जबकि पटरी से 30 मीटर तक कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। शहर के बीचोंबीच करोड़ों रुपये मूल्य की इस बेशकीमती जगह को पट्टे पर दिये जाने के मुद्दे को सांसद कुमारी सैलजा ने भी उठाया था।

सिरसा में डबवाली रोड पर रेलवे की काफी जमीन वर्षों से खाली पड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक मिलीभगत कर इस जमीन को 99 सालों के लिए पट्टे पर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त जमीन को 32 करोड़ रुपये में दिया गया है जबकि अब वहां पर भारी-भरकम राशि का प्रोजेक्ट बनाकर कॉमर्शियल मार्केट की तैयारी चल रही है। चर्चाएं हैं कि यहां एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। इस मार्केट में एंट्री के लिए कंपनी ने डबवाली रोड पर एक चिकित्सक से बिल्डिंग खरीद कर उसे समतल कर दिया और वहां से गेट बना दिया गया। इतना ही नहीं इसके साथ लगती कई एकड़ जमीन पर

भी कब्जा किया हुआ है।

रेलवे पटरी के साथ एक आलीशान पार्क भी न जाने किसने विकसित कर दिया और उसमें लाइटिंग, घास इत्यादि लगा दी। बताया जा रहा है कि रेलवे ने तो इसे बनाया नहीं। वर्णनीय है कि इससे पहले यहां एक क्लब ने पार्क बनाना शुरू किया था, जिसे रेलवे ने रुकवा दिया था। यहां पर लंबे-चौड़े एरिया में पार्किंग स्थल बनाकर पेड पार्किंग भी शुरू की गई है और लोगों से प्रति गाड़ी के हिसाब से रुपये वसूल किए जा रहे हैं।खास बात यह है कि पार्किंग संचालक दावा कर रहे हैं कि इस वसूली जाने वाली राशि में से सिरसा में चल रहे एक बेसहारा आश्रम को भी दी जा रही है।

कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को चार फीसदी आरक्षण पर नया बवाल

न्यूज़ डेस्क

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता यानी केटीपीपी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी ने इसका विरोध किया है। बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने सरकारी परियोजनाओं में मुस्लिम ठेकेदारों का चार फीसदी आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने इसे कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति बताया और चेतावनी दी कि इसका देशव्यापी असर होगा। भाजपा ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस कई चुनाव हारने के बावजूद अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रही है।

प्रसाद ने कहा, यह कर्नाटक का मामला है, लेकिन इसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव होगा। यह कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि अब तक हम केवल नौकरियों में आरक्षण की बात करते थे, लेकिन अब सरकारी ठेकों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। उसमें भी चार फीसदी मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा धर्म के आधार पर आरक्षण के पूरी तरह खिलाफ है और इसका विरोध करती रहेगी। उन्होंने आगे कहा, भाजपा इसके खिलाफ है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान के तहत मान्य नहीं है। सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरह असंवैधानिक है। इसे केवल सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी धार्मिक समुदाय को सीधे तौर पर देना मान्य नहीं है।

कर्नाटक सरकार के इस फैसले के कारण नई सियासी बहस शुरू हो गई है। भाजपा ने इसे सांप्रदायिक पक्षपात करार दिया है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का कहना है कि यह कदम आर्थिक अवसरों में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्रसाद ने कर्नाटक सरकार और कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला किया और मुस्लिम ठेकेदारों के लिए चार फीसदी आरक्षण के फैसले के लिए कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राजनीतिक लाभ के लिए इस कदम को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रसाद ने कहा, वे कई बार हारने के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं। कर्नाटक में यह आरक्षण राहुल गांधी के संरक्षण में बढ़ाया गया है। सिद्धारमैया इसमें खुद इसकी घोषणा करने की न तो हिम्मत है और न ही राजनीतिक ताकत। उन्होंने आगे राहुल गांधी पर वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी सोचते हैं कि वह इस वोट बैंक की राजनीति से नेतृत्व कर सकते हैं। कांग्रेस जो तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के नए मानक स्थापित कर रही है, वे देश के लिए हानिकारक हैं।

तेलंगाना : ओबीसी के लिए 42% आरक्षण का ऐलान

न्यूज़ डेस्क

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के ऐलान के बाद बीते सोमवार को विधानसभा में ओबीसी के लिए 42 फीसदी सीटें आरक्षित करने का बिल पास हो गया। इसके साथ ही तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने एक बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया।बता दें कि बिहार के बाद तेलंगाना दूसरा ऐसा राज्य है, जिसने जातिगत सर्वे कराया है।

बता दें कि सीएम रेवंत रेड्डी ने सत्ता में आने के बाद जाति जनगणना कराने का ऐलान किया था। पार्टी ने कहा था कि वह जनगणना के बाद ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाएगी। जातिगत सर्वे में ओबीसी की संख्या 56.33 फीसदी सामने आई थी। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में नए जाति सर्वेक्षण का संक्षिप्त विवरण पेश किया था।

सीएम रेड्डी ने शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी समुदाय के लिए 42 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी पोस्ट में लिखा, तेलंगाना को गर्व है कि वह भारत में सामाजिक क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि हम भारतीय स्वतंत्रता के बाद से पिछड़े वर्गों की सबसे लंबी मांग को पूरा कर रहे हैं। हमारे भाई-बहन जो पिछड़े वर्गों से आते हैं, उनकी यह मांग थी कि उन्हें आधिकारिक जनगणना में गिना और पहचाना जाए और आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं।' उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'देश के इतिहास में पहली बार, हमने कमजोर वर्गों का हिसाब चुका दिया है। हम अधिकारों को वैधता दे रहे हैं।'

विधानसभा में रेवंत रेड्डी सरकार की तरफ से बीते सोमवार को तेलंगाना पिछड़ा वर्ग (ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण) विधेयक, 2025 पेश किया गया। इस बिल को चर्चा के बाद पास कर दिया गया।

सीएम रेवंत रेड्डी ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह एक बड़ा कदम है, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव लाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सरकार के इस फैसले के बाद तेलंगाना के ओबीसी समुदाय को विभिन्न सरकारी सेवाओं और अवसरों में समान भागीदारी मिलेगी।

क्या जनसंख्या नियंत्रण वाले राज्यों के लिए घातक है परिसीमन ?

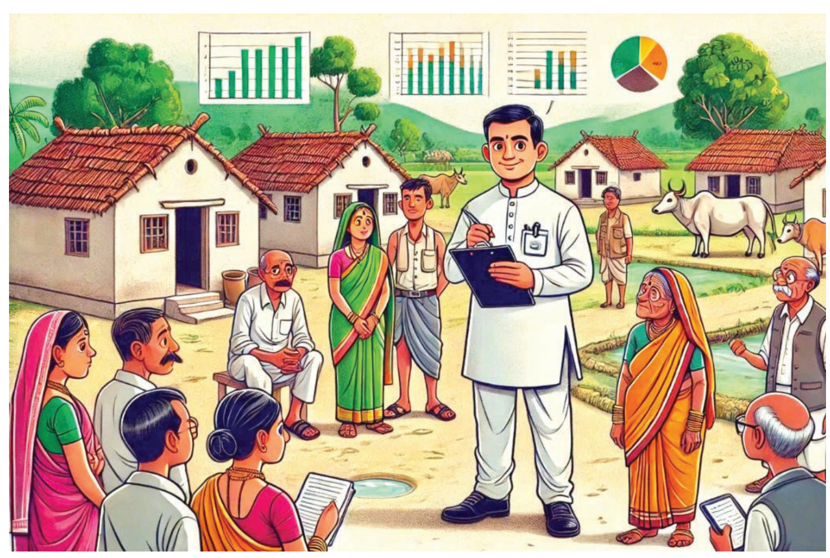

न्यूज़ डेस्क

द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके सांसद पी विल्सन ने राज्यसभा में कहा कि मौजूदा समय में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन लागू करना उन राज्यों के लिए अन्याय होगा। जिन्होंने जनसंख्या पर काबू पाया. उनके मुताबिक, यह कदम जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को दंडित करेगा और इसमें नाकाम रहे राज्यों को फायदा पहुंचाएगा। विल्सन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक समग्र परिसीमन नीति की मांग की। विल्सन ने बताया कि 1952, 1962 और 1972 में जनगणना के बाद परिसीमन हुआ था, ताकि सभी राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व हो। लेकिन कुछ राज्यों ने परिवार नियोजन को गंभीरता से लिया, जबकि अन्य ने इसे नजरअंदाज किया, जिससे उनकी आबादी बेलगाम बढ़ी। 42वें संवैधानिक संशोधन ने 1971 की जनगणना के आधार पर 25 साल तक परिसीमन टाला, जो 2000 में 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसका मकसद जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना था। फिर भी, तमिलनाडु (1.7) और केरल (1.8) जैसे राज्यों ने प्रजनन दर को सीमित किया, जबकि उत्तर प्रदेश (2.4) और बिहार (3.0) में जनसंख्या वृद्धि जारी है।

विल्सन ने कहा कि 2026 में परिसीमन की रोक हटाने का मूल तर्क अब सही नहीं लगता। अगर यह लागू हुआ, तो तमिलनाडु जैसे राज्य, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रित की, उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि 2026 की जनगणना के आधार पर राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को 150 से ज्यादा अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं, जबकि दक्षिणी राज्य—तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना—केवल 35 सीटें ही पा सकेंगे। अगर मौजूदा 543 सीटें पुनर्वितरित हुईं, तो तमिलनाडु को 8 सीटों का नुकसान और उत्तर प्रदेश-बिहार को 21 सीटों का फायदा होगा। द्रमुक सांसद ने कहा कि यह बदलाव उन राज्यों के खिलाफ होगा, जिन्होंने राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति को अपनाया। इससे तमिलनाडु जैसे राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और ताकत कम होगी, जबकि परिवार नियोजन से मुंह मोड़ने वाले राज्य लाभ में रहेंगे। विल्सन ने सवाल उठाया, "हमें अपना हक और राजनीतिक लाभ क्यों गंवाना पड़े? जो राज्य राष्ट्रीय सोच के साथ चले, उनके खिलाफ यह राजनीतिक तख्तापलट क्यों?" विल्सन ने संसद से आग्रह किया कि परिसीमन को सिर्फ आंकड़ों का खेल न बनाया जाए। उनके मुताबिक, यह नीति उन राज्यों के लिए 'आपदा' बन सकती है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई। उन्होंने कहा, "हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो मेहनत करने वालों को सजा न दे और नाकामियों को इनाम न बांटे." यह मुद्दा संसद में गहरी बहस की मांग करता है, ताकि सभी राज्यों के साथ न्याय हो सके।

योगी जी के राज में सामने आया हाथरस कॉलेज की कलंक गाथा

न्यूज़ डेस्क

यूपी का हाथरस जिला अपनी बेवसी पर फिर आंसू बहा रहा है। हाथरस पहले कई बार जघन्य कृत्य के लिए शर्मसार रहा है लेकिन इस बार जिस तरह की कलंक गाथा सामने आयी है वह शिक्षा जगत को तो कलंकित और शर्मसार करती ही है। सीएम योगी सरकार द्वारा महिला और छात्राओं की संरक्षा और सुरक्षा की गारंटी की भी कलई खोलती है। हाथरस के पीसी बगला डिग्री कॉलेज के भीतर छात्राओं को लोभ लालच और डराकर यौनाचार की जो कहानी सामने आयी है वह शिक्षा जगत को तो बदनाम कर ही रही है ,हाथरस के उन अभिभावकों को भी शर्मसार किये हुए हैं जो अपनी बेटियों को बड़ी आस के साथ बगला कॉलेज में पढ़ने को भेज राहे थे।

गौरतलब है कि पीसी बागला डिग्री कॉलेज के भूगोल विभाग के अध्यक्ष डॉ. रजनीश के खिलाफ छात्राओं का यौन शोषण करने का मामला थाना हाथरस गेट में दर्ज किया गया है। इस मामले में शहर के एक मोहल्ला निवासी छात्रा ने भी डीएम से शिकायत की है, जिस पर उन्होंने एक चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इस समिति में एसडीएम सदर नीरज शर्मा अध्यक्ष, सीओ योगेंद्र कृष्ण नारयण, तहसीदार चंद्र प्रकाश सिंह व बीएसए स्वाति भारती को सदस्य बनाया गया है। यह बात और है कि आरोपी रजनीश को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जब साल भर पहले ही कॉलेज की कई लड़कियों ने यौन शोषण की शिकायत थाने में लिखित रूप से की थी ,तब इसकी जांच क्यों नहीं की गई। जाहिर है थाना भी इस मामले को जानते हुए भी रफा दफा करने पर तुली थी। यही से योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक़ पीसी बागला डिग्री कॉलेज के भूगोल विभाग के अध्यक्ष डॉ. रजनीश के छात्राओं का यौन शोषण करने से संबंधित 59 वीडियो व फोटो सामने आए हैं। इनमें दिख रहे चेहरों का कॉलेज के डाटाबेस से मिलान किया जा रहा है ताकि छात्राओं की पहचान कर उनसे संपर्क किया जा सके। पीड़ित छात्राएं लोक-लाज के चलते सामने आने से बच रही हैं। जो वीडियो और फोटो सामने आए हैं, उनमें अलग-अलग छात्राएं दिख रही हैं। इनमें कुछ कॉलेज की यूनिफॉर्म में है। हाथरस में पीसी बागला डिग्री कॉलेज के भूगोल विभाग के प्रभारी डॉ. रजनीश की छात्राओं के साथ जो अश्लील वीडियो सामने आई हैं, वह प्रोफेसर ने खुद अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड की थीं। ऐसे लगभग 59 वीडियो मिले हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इनमें से कुछ वीडियो उनके द्वारा अश्लील वेबसाइट्स पर भी अपलोड की गई हैं। बड़ी बात तो यह भी है कि कुछ तस्वीर डीन के कमरे की भी है। ऐसे में यह भी आशंका हो रही है कि दुराचार के इस खेल में ऊपर से नीचे तक के कर्मचारी शामिल रहे हैं। खबर तो यह भी मिल रही है कि कॉलेज के भीतर यौनाचार का यह खेल 20 वर्षों से चल रहा था।

जानकारी के मुताबिक़ करीब एक महीने पहले केंद्रीय महिला आयोग सहित तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पास एक गुमनाम शिकायती पत्र भेजा गया था। इसमें पीसी बागला डिग्री कॉलेज के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कालेज के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉ. रजनीश के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। कुछ दिनों तक सीओ सिटी ने इस शिकायती पत्र को लेकर जांच पड़ताल की। कई लोगों से बुलाकर जानकारी की। पुलिस के पास शिकायती पत्र के साथ करीब बारह फोटो भेजे गए थे। इसमें से कुछ फोटो कॉलेज के अंदर के ऑफिस के हैं। इन फोटो में प्रोफेसर डॉ. रजनीश कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लीलता करता दिख रहा है। पुलिस ने फोटो में दिख रही छात्राओं के नाम पता जानने की कोशिश की, लेकिन कालेज प्रशासन की ओर से पुलिस को कोई सहयोग नहीं दिया गया।

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने इस मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह से कराई है। एएसपी को जांच के दौरान शिकायत में कुछ तथ्य सही भी मिले। उन्होंने अपनी रिपोर्ट एसपी को भेज दी। पुलिस ने इस मामले के वायरल होने के बाद हाथरस गेट कोतवाली के औद्योगिक चौकी इंचार्ज सुनील कुमार की ओर से प्रोफेसर डॉ. रजनीश के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस आरोपी प्रोफेसर की तलाश कर रही है।प्रोफेसर द्वारा छात्राओं के यौन शोषण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब पुलिस इस मामले से जुड़ी पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज करने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है। लेकिन, छात्राएं लोक-लाज के चलते बयान दर्ज कराने से बच रही हैं।

जानकारी के मुताबिक़ डॉ. रजनीश परीक्षाओं में नंबर बढ़वाने और नौकरी लगवाने के नाम पर छात्राओं को अपनी बातों में उलझा लेता था। प्रोफेसर खुद ही अपने मोबाइल से छात्राओं के वीडियो रिकॉर्ड करता था। प्रोफेसर के मोबाइल से करीब 59 वीडियो वायरल हुई हैं।

30 अप्रैल से होगा चार धाम यात्रा का आगाज

न्यूज़ डेस्क

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक़ गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल के पूरे विधि- विधान से साथ खोल दिए जाएंगे। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और श्रीबदरीनाथ धाम के कपाट 4 मई को पूरे विधि-विधान से साथ खोल दिए जाएंगे। चारधाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ,बसे जरूरी चीज है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हिमालय की पावन व पुण्यदायी चारधाम यात्रा के लिए आधार कार्ड आधारित ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ हो गया है। यह यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ विधिवत रूप से प्रारंभ होगी। इसके उपरांत दो मई को केदारनाथ धाम तथा चार मई को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं, सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 25 मई को श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे।

उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, जिससे तीर्थयात्रियों को उनके निर्धारित तिथि पर सुगमतापूर्वक दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था के माध्यम से धामों में भीड़ नियंत्रण एवं श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।चारधाम यात्रा को सफल एवं व्यवस्थित बनाने हेतु प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा मार्गों की मरम्मत, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था एवं यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर मेडिकल कैंप, आपातकालीन सेवा केंद्र एवं अन्य सुविधाएं स्थापित की गई हैं। चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक आस्था एवं आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत से जुड़ने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करती है।श्रद्धालुओं को अपने निर्धारित तिथि पर यात्रा करने हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया को समय पर पूर्ण करने की सलाह दी जाती है, जिससे वे अपने आध्यात्मिक सफर का आनंद निर्बाध रूप से उठा सकें। श्रद्धालुओं को सरकार की तरफ से कुछ सलाह भी दी गई है। कहा गया है कि पंजीकरण के दौरान सही मोबाइल नंबर दर्ज करें। धामों में दर्शन टोकन अवश्य प्राप्त करें। यात्रा के दौरान ऊनी कपड़े, छतरी, रेनकोट आदि साथ रखें। वरिष्ठ नागरिक यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। पंजीकरण प्रक्रिया में सटीक जानकारी दर्ज करें। हेली टिकट प्रदान करने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों से बचें। धामों में दर्शन कराने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों से बचें। और यात्रा के दौरान जरूरी दवाएं अपने पास रखें।

विधानसभा क्षेत्र विकासनगर अब चारधाम यात्रा मार्ग के महत्वपूर्ण स्थलों में अपनी जगह बना चुका है। इस वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में दो नए चेकपोस्ट बनाए जाएंगे।ये चेकपोस्ट कटापत्थर और हरबर्टपुर बस अड्डे पर स्थापित किए जाएंगे, जिससे तीर्थयात्रियों के वाहनों की सुचारू जांच संभव हो सकेगी एआरटीओ कार्यालय द्वारा इस योजना की संपूर्ण तैयारी की जा चुकी है और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। पिछले वर्ष यात्रा सीजन के दौरान कटापत्थर चेकपोस्ट पर भारी जाम की समस्या उत्पन्न हो गई थी। केवल एक चेकपोस्ट होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई थीं, जिससे तीर्थयात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था।इसके अलावा, मसूरी-कैंपटी रोड पर ट्रैफिक प्रतिबंधित होने के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की ओर जाने वाले वाहनों की भीड़ शुरू में ही अत्यधिक बढ़ गई थी, जिससे यात्रा व्यवस्था चरमरा गई थी।

क्या अब मायावती का इकबाल ख़त्म हो रहा है ?

राजनीतिक डेस्क

सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अगले यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा कोई कमाल दिखा पायेगी ? लेकिन यह सवाल तो तब है जब बसपा का संगठन काम करता रहेगा। जिस तरह की जानकारी मिल रही है उससे तो यही लगता है कि बसपा प्रमुख मायावती इन दिनों बेहद खामोश हैं और वह कई मसलों पर चिंतन कर रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कई तरह की बाते सामने आती है और फिर बसपा के संगठन की कमजोरी को लेकर भी खबरे आती रहती है। ऐसे में कुछ सवाल और भी खड़े होते हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बसपा टूट जायेगी। लेकिन कुछ लोग इससे आगे की बात भी करते हैं कि बसपा बीजेपी के साथ चली जाएगी। लेकिन ये सब कयास भर ही हैं। बसपा को लेकर मायावती क्या प्लानिंग कर रही है यह किसी को पता नहीं। लेकिन बसपा के भीतर कोहराम तो मचा ही हुआ है। कुछ बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं तो कुछ नेताओं को मायावती खुद ही बाहर करती दिख रही है। पार्टी को आगे कौन नेता राह देगा यह सब अँधेरे में है। असली बात तो यही है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। लगातार घटते जनाधार के बीच पार्टी के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठने लग गए हैं। सवाल उठ रहे हैं की क्या कांशीराम की बसपा अब अपने अंतिम दौर में है? क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव बसपा के ताबूत में आखिर किल साबित होगा ? तमाम सवाल है लेकिन इन सभी का जवाब भविष्य के गर्भ में है।

पिछले एक दशक में अर्श से फर्श के सफर में बसपा की गिरावट के लिए कई कारण गिनाए जाते हैं लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह ब्राह्मणों का उससे दूर हो जाना है। मायावती ने 2007 में जिस ब्राह्मण-दलित गठबंधन के दम पर सत्ता हासिल की थी, वही गठबंधन बाद में उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। बसपा की पारंपरिक राजनीति दलित केंद्रित रही थी, लेकिन 2007 के चुनावों में मायावती ने 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की नीति अपनाई और ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचा। सतीश चंद्र मिश्रा को आगे कर उन्होंने ब्राह्मणों को बसपा से जोड़ने का प्रयास किया। नारा दिया गया 'ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा', जिससे ब्राह्मणों को यह संदेश गया कि वे भी सत्ता में भागीदार रहेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि बसपा ने 2007 के चुनाव में 40.43% वोट शेयर के साथ 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2012 के चुनावों तक आते-आते यह गठबंधन बिखरने लगा। सरकार बनने के बाद बसपा ने ब्राह्मणों को सिर्फ शोपीस बनाकर रखा, लेकिन उन्हें कोई ठोस राजनीतिक फायदा नहीं मिला। पार्टी में निर्णय लेने की ताकत सिर्फ मायावती और उनके करीबी नेताओं तक सीमित रही। 2012 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक सपा की ओर खिसका तो बसपा 80 सीटों पर सिमट गई लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा ने ब्राह्मणों को हिंदुत्व और विकास के एजेंडे के तहत अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद यह वोट बैंक तेजी से भाजपा के पक्ष में चला गया। 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा 19 सीटें ही जीत पाई। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में तो बसपा की ऐसी किरकिर हुई की पार्टी महज एक सीट ही जीत पाई।

साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा ने ब्राह्मण के बीच खोए हुए जनाधार को पाने के लिए फिर से कोशिश की। मायावती ने फिर से ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन किया लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 2014 में मोदी के हिंदुत्व वाले एजेंडे में ब्राह्मणों अपने लिए मुफीद माना और भाजपा के साथ खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए आखिरी मौका हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस चुनाव में बसपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो पार्टी पूरी तरह हाशिए पर चली जाएगी क्योंकि भाजपा और सपा ने बसपा के पारंपरिक वोट बैंक में गहरी सेंध लगा दी है। चंद्रशेखर आज़ाद नए दलित नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं।

न्यू देहली पोस्ट

काला धतूरा : जहरीला भी है लेकिन औषधीय गुणों से भरपूर भी

हेल्थ डेस्क

वैसे तोई काला धतूरा जहरीला होता है लेकिन इसके सही उपयोग से चमत्कारिक लाभ भी मिलते हैं। इसे औषधीय पौधा कहा जाता है।वैज्ञानिक शोध में इसे फायदेमंद बताया गया है।इसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है। रिसर्च जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोडायनामिक्स के शोध में पाया गया कि काले धतूरे में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक (दर्द निवारक) गुण होते हैं, जो कई रोगों के इलाज में सहायक हो सकते हैं। शोध के अनुसार, काले धतूरे के बीज और पत्तों का धुआं दमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस संबंधी समस्याओं में राहत दे सकता है।

काले धतूरे के कमाल के फायदे

इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व सिरदर्द, जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी समस्याओं में राहत दिलाने में सहायक हो सकते हैं। पारंपरिक चिकित्सा में फोड़े-फुंसी, खुजली और त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शोध में भी पाया गया कि इसमें एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा रोगों में फायदेमंद हो सकते हैं। काले धतूरे के कुछ तत्व मांसपेशियों को आराम देने और ऐंठन को कम करने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में इसे पाचन सुधारने, बुखार कम करने और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए उपयोग किया जाता रहा है।

आरजेपीपीडी के शोध के अनुसार, धतूरे के पत्तों का स्वाद कड़वा होता है और धतूरे के बीजों जैसी ही गंध होती है। इसका उपयोग एनोडीन और एंटीस्पास्मोडिक के रूप में भी किया जाता है। यह पौधा तीखा, मादक, दर्द निवारक, नशीला और उल्टी लाने वाला होता है। यह कई प्रकार की बीमारियों में फायदेमंद बताया गया है। अस्थमा, खांसी, बुखार, सूजन, नसों का दर्द, पागलपन, मांसपेशियों में दर्द, हाइपरएसिडिटी, अल्सर, किडनी का दर्द और पथरी में इसके उपयोग की सलाह दी जाती है। इसके जड़ों का उपयोग पागल कुत्तों के काटने पर किया जाता है। पत्तियों का प्रयोग सूजन और बवासीर में होता है और इनका रस जूं और त्वचा रोगों के उपचार के लिए बाहरी रूप से लगाया जाता है। पत्तियों को पुल्टिस के रूप में कटिवात, साइटिका, नसों के दर्द, कण्ठमाला और दर्दनाक सूजन में उपयोग किया जाता है।

चेतावनी

शोधकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि काले धतूरे का ज्यादा सेवन जहरीला हो सकता है और इसके कुछ रासायनिक तत्व नर्वस सिस्टम पर असर डाल सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, गलत तरीके से सेवन करने पर यह मतिभ्रम, उल्टी, हार्ट रेट में गड़बड़ी और गंभीर मामलों में मौत का कारण भी बन सकता है।

प्रकृति का अनमोल उपहार है महुआ

हेल्थ डेस्क

भारत के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले महुआ का नाम सुनते ही एक मीठी सुगंध और बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। महुआ का वैज्ञानिक नाम है मधुका लॉन्गीफोलिया। यह एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल और फल दोनों ही स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए लाभकारी हैं। यह पेड़ न केवल पोषण देता है, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा और सांस्कृतिक प्रथाओं में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। कई पारंपरिक गीतों और कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। स्वास्थ्य और संस्कृति का अभिन्न अंग होने के साथ यह महुआ प्रकृति का श्रृंगार भी करता है क्योंकि जब आम में मंजरी (बौर) और महुआ में कूंच (कली) एक साथ खिलते हैं, तो यह संकेत होता है बसंत ऋतु का आगमन होने जा रहा है। महुआ के फूल रात भर पेड़ से टपकते हैं। महुआ के बड़े-बड़े बगीचों को "मऊहारी" कहा जाता है जो अब पहले की तुलना में कम देखने के लिए मिलते हैं।

महुआ के फूल सुगंधित और मीठे होते हैं, जिनमें उच्च मात्रा में शर्करा होती है। इस वजह से इन्हें ताजा खाए जाने पर स्वाद किसी मिठाई सा होता है और सूखने पर यह किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट सरीखे हो जाते हैं। अपनी मिठास के चलते महुआ के ताजे फूलों से पकवान भी बनाए जाते हैं। इन मिठास से भरे फूलों का रस निकालकर उसमें आटा गूंथकर ठकुवा, लापसी आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। सूखे फूलों को भूनकर और ओखली में कूटकर "लाटा" बनाया जाता है, जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। इस तरह से महुआ के फूल ताजा या सुखाकर भी खाए जाते हैं और इनसे कई व्यंजन बनाए जाते हैं। ऐसे ही तिनछठी व्रत में भी महुआ के सूखे फूलों का इस्तेमाल प्रसाद बनाने में होता है।

मार्च से अप्रैल तक आने वाले महुआ के फूलों का उपयोग पारंपरिक रूप से गाय-भैंसों को खिलाने के लिए भी किया जाता है, जिससे दूध उत्पादन बढ़ता है। इसके अलावा, इन फूलों का इस्तेमाल करके किण्वन प्रक्रिया से "महुआ शराब" भी बनाई जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है। हालांकि महुआ के फूल और फल आमतौर पर सुरक्षित हैं, फिर भी अधिक मात्रा में महुआ शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण महुआ के फूल औषधीय गुणों की भी खान हैं। यह फूल ऊर्जा बढ़ाने के साथ-साथ श्वसन समस्याओं जैसे सर्दी, खांसी और ब्रोंकाइटिस में राहत प्रदान कर सकते हैं। सूखे फूलों को भिगोकर पीसकर बांधने से सूजन, दर्द और मोच में राहत मिलती है। फूलों का मौसम खत्म होने के बाद महुआ के पेड़ पर इसके फल "कोइन" की बारी आती है। महुआ के बीज में काफी मात्रा में तेल होता है जिसके विविध उपयोग हैं। एक तरफ यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है तो साबुन, डिटर्जेंट आदि बनाने में भी इसके तेल का उपयोग होता है। इस तरह से महुआ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि प्रकृति का वह उपहार है जो स्वास्थ्य, स्वाद और संस्कृति को एक साथ जोड़ता है। इसके फूलों की मिठास हो या फलों का औषधीय गुण, महुआ हर रूप में जीवन को समृद्ध करता है।

गर्भावस्था में धूम्रपान का असर कोख में पलने वाले लड़कों पर ज्यादा

हेल्थ डेस्क

हालिया शोध से पता चला है कि गर्भवती स्त्री के धूम्रपान का असर कोख में पलने वाली लड़की से ज्यादा लड़के पर होता है। गर्भवती महिलाओं के धूम्रपान का उनके बच्चे पर होने वाला असर इतना अधिक है कि अगर उनकी संतान खुद भी धूम्रपान करने लगे तो उसकी युवावस्था में ही मौत हो सकती है। एबरदीन यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों की एक टीम ने ब्रिटेन के 5 लाख से ज्यादा लोगों पर रिसर्च करके इस बारे में जानकारी हासिल की है। रिसर्चर ये पता लगाना चाहते थे कि गर्भावस्था में धूम्रपान का कोख में पलने वाले बच्चे पर क्या असर होता है और यह असर बच्चों के वयस्क होने तक कैसे जारी रहता है। रिसर्च टीम का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर पॉल फाउलर यूनिवर्सिटी में ट्रांसनेशनल मेडिकल साइंसेज के चेयरैमन हैं। उन्होंने मां और उनके वयस्क बच्चों के बीच जेनेटिक संबंधों का इस्तेमाल कर गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान के असर का व्यापक विश्लेषण किया है। पहली बार इतने बड़े स्तर पर इस विषय में रिसर्च की गई है।

रिसर्चरों ने जीन के कई प्रारूप की पहचान की है जो मातृत्व के दौरान धूम्रपान की संभावना को बढ़ा देते हैं। लोगों को धूम्रपान से रोकने के लिए होने वाले खास इलाजों को तैयार करने में इस रिसर्च के नतीजे उपयोगी होंगे. स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के 22 सेंटरों से 5 लाख से ज्यादा लोगों के आंकड़े इस रिसर्च के लिए जुटाए गए। इनके जरिए टीम ने ये पड़ताल की है कि गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान से कौन से जेनेटिक, बायोकेमिकल और सामाजिक और आबादी से जुड़े कारक जुड़े होते हैं। उन्होंने देखा कि हर चरण में नर भ्रूण और वयस्क बेटे मां के धूम्रपान से महिलाओं की तुलना में ज्यादा प्रभावित होते हैं। उन्होंने नर भ्रूण के लीवर में कई जीनों के स्तर में बदलाव को 17 हफ्तों की गर्भावस्था से लेकर वयस्क पुरुषों तक देखा जो उनकी जीवन प्रत्याशा को घटाती है। टीम को पता चला कि अगर वयस्क पुरुष धूम्रपान छोड़ दें या फिर बिल्कुल ना करें तो वे इस जोखिम का सामना कर सकते हैं। युवावस्था में मौत की आशंका उन लोगों में कम हो गई जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी।

रिसर्च में यह भी पता चला है कि पुरुषों में वयस्क होने के बाद कैंसर और दो तरह के डायबिटीज होने की आशंका भी महिलाओं की तुलना में ज्यादा होती है। महिलाओं में मां के धूम्रपान के असर से पाचन और प्रजनन के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की ज्यादा आशंका रहती है। मिहाइल मिहोव ने यह रिसर्च अपनी पीएचडी रिसर्च के लिए की थी। उनका कहना है, "गर्भावस्था के दौरान मातृत्व धूम्रपान बच्चों के लिए कई समस्याओं का कारण बनता है। हालांकि पहले इस बात की जानकारी नहीं थी कोख में कौन सी प्रक्रिया पर मातृत्व धूम्रपान का असर होता है और बाद में वो कैसे स्वास्थ्य को कमजोर करते हैं। "

लाल चन्दन की खेती से बन सकते हैं करोड़पति

कृषि डेस्क

आपने चंदन के बारे में तो सुना ही होगा। चंदन का उपयोग भगवान के पूजन से लेकर शर्बत बनाने सहित इत्र निर्माण तक में किया जाता है। इसकी बाजार में बहुत मांग रहती है। यदि सही तरीके से इसकी खेती की जाए तो इससे किसान लाखों रुपए कमा सकते हैं। बता दें कि भारत में दो प्रकार के चंदन की खेती की जाती है एक सफेद चंदन और दूसरा लाल चंदन। लाल चंदन का उपयोग भगवान की पूजा से लेकर मूर्तियां बनाने, फर्नीचर निर्माण सहित अनेक प्रकार के कार्यों में किया जाता है। इससे मार्केट में लाल चंदन की डिमांड बहुत रहती है और इस कारण इसको बेचने पर काफी अच्छे भाव मिलते हैं। इस लिहाज से लाल चंदन की खेती करना लाभ का सौदा बनता जा रहा है।

क्यों करें लाल चंदन की खेती?

लाल चंदन को जंगली पेड़ माना जाता है। लाल चंदन को कई नामों से जाना जाता है। इसे अल्पगु, सौंडरवुड, रेड सैंडर्स, रेड सैंडर्सवुड, रेड सॉन्डर्स, रक्त चंदन, लाल चंदन, रगत चंदन, रुखतो चंदन आदि नामों से पहचाना जाता हैं। लाल चंदन के पेड़ का वैज्ञानिक नाम पटरोकार्पस सैंटालिनस है। यह भारत के पूर्वी घाट के दक्षिणी भागों में पाया जा सकता है। इसके पेड़ को कम देखभाल की जरूरत होती है। यदि किसान इसकी खेती करें तो काफी मुनाफा कमा सकता है। माना जाता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक टन लकड़ी की कीमत 20 से 40 लाख रुपए के बीच होती है। लाल चंदन और इसकी लकड़ी से बने उत्पादों की विशेष रूप से चीन और जापान जैसे देशों में भारी मांग है। वहीं इसकी घरेलू मांग भी बहुत है। लाल चंदन का प्रत्येक पेड़ 500 किलोग्राम 10 साल की उपज देता है। बता दें कि लाल चंदन के पेड़ की प्रजाति का विकास बेहद धीमी गति से होता है और सही मोटाई हासिल करने में कुछ दशक लग जाते हैं।

विशेषताएं और उपयोग

लाल चंदन एक छोटा पेड़ है, जो 5-8 मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है और यह गहरे लाल रंग का होता है। लाल चंदन की लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से नक्काशी, फर्नीचर, डंडे और घर के लिए किया जाता है। इसका उपयोग संगीत वाद्ययंत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा लाल चंदन की लकड़ी का उपयोग सैंटालिन, दवा और सौंदर्य प्रसाधन के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। मंदिरों और घर पर लोग पूजा में भी लाल चंदन का उपयोग करते हैं।

उपयोगी मिट्टी और जलवायु

लाल चंदन की खेती के लिए शुष्क गर्म जलवायु में अच्छी रहती है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमद मिट्टी अच्छी रहती है। मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 6.5 पीएच होना चाहिए। बता दें कि लाल चंदन की खेती रेतीले और बर्फीले इलाकों में संभव नहीं है।

खेती का उचित समय

जैसा कि लाल चंदन की खेती के लिए शुष्क गर्म जलवायु अच्छी मानी जाती है। इस लिहाज से देखें तो भारत में इसकी खेती के लिए सबसे उचित समय मई से जून तक का माना जाता है।

लगाएं होस्ट का पौधा

लाल चंदन के साथ होस्ट का पौधा लगाना अच्छा रहता है। बताया जाता है कि होस्ट की जड़ें, लाल चंदन की जड़ों जैसी होती है इसलिए इसका पौधा इसके साथ लगाना चाहिए। इससे लाल चंदन के पौधे का विकास तेजी से होता है। होस्ट के पौधे को चंदन के पौधे से 4 से 5 फुट की दूरी पर लगाना चाहिए।

पौधा और कीमत

लाल चंदन का पौधा किसानों को सरकारी या प्राइवेट नर्सरी से 120 रुपए से 150 रुपए तक में मिल जाएगा। इसके अलावा इसके साथ लगने वाले होस्ट के पौधे की कीमत करीब 50 से 60 रुपए होती है।

खेत की तैयारी

लाल चंदन की खेती के लिए भूमि की बार-बार जुताई की जाती है। सबसे पहले खेत की एक से तीन बार ट्रैक्टर से जुताई करें। इसके बाद एक बार कल्टीवेटर से खेत की जुताई कर खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना लें। इसके बाद खेत को समान करने के लिए पाटा लगाएं। अब खेत में 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी आकार के साथ 4 मीटर & 4 मीटर की दूरी पर गड्ढे खोदे जाते हैं। लाल चंदन के पौधे दो 10 x10 फीट की दूरी में लगाया जा सकता है। यदि आप पेड़ लगा रहे तो कभी भी लगा सकते हैं लेकिन यदि पौधा लगाते हैं तो दो से तीन वर्ष का पौधा लगाना ही बेहतर रहेगा। इससे एक फायदा ये होगा कि आप इसे किसी भी मौसम में लगा सकेंगे और इसकी देखभाल भी कम करनी होगी। इसके पौधों को निचले स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। इसलिए इसे खेतों की मेड़ पर लगाया जा सकता है। मेड को ऊंचा रखें ताकि लाल चंदन के पौधे के पास पानी का जमाव नहीं हो सकें।

खाद एवं उर्वरक

बारिश के शुरुआती मौसम में 2-3 टोकरी गोबर की सड़ी हुई खाद, 2 किलो नीम की खली, 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर गड्ढा भर देना चाहिए। बरसात के मौसम के बाद थाला बनाकर आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए।

सिंचाई प्रबंधन

चंदन के पौधों को हफ्ते में 2 से 3 लीटर पानी की जरूरत होती है। जानकारों के मुताबिक चंदन के पेड़ को पानी के लगने से ही बीमारी होती है। इसलिए चंदन के पौधों को जल भराव की स्थिति से बचाना चाहिए। इसलिए खेत में ऐसी व्यवस्था करें की लाल चंदन के पौधे के पास जल का भराव न हो। वहीं बात करें इसकी सिंचाई की तो इसके पौधों की रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद मौसम की स्थिति के आधार पर 10-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की जा सकती है।

खरपतवार नियंत्रण के उपाय

जैसा कि सभी फसलों में खरपतवार का प्रकोप होता है। वैसे ही लाल चंदन के पौधों के आसपास भी खरपतवार उग आती है जो पौधे के विकास में बाधक होती है। इसलिए समय-समय पर खरपतवारों को खेत से निकाल कर कहीं दूर फेंक देना चाहिए। लाल चंदन के पौधे को पहले दो साल तक खरपतवार से मुक्त रखना जरूरी है। लाल चंदन के पेड़ में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप होता है। यह इल्ली अप्रैल से मई तक फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए साप्ताहिक अंतराल पर दो बार 2 प्रतिशत मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करके इस पर नियंत्रण किया जा सकता है।

झींगा पालन से हो सकती है 15 लाख प्रति एकड़ की कमा

कृषि डेस्क

पूरी दुनिया में सी फ़ूड की बहुत ज्यादा मांग है। जिसमें से एक समुद्री जीव झींगा भी है, परन्तु मांग के कारण आज समुद्रों से झींगा पकड़ना बहुत महंगा पड़ता है और आपूर्ति करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने भारत में भी झींगा पालन का व्यवसाय बहुत तेजी से हो रहा है। देश के किसान इससे काफी मुनाफा भी कमा रहे हैं। झींगा एक समुद्री समुद्री जीव है | इसका वैज्ञानिक नाम पेनियस मोनोडॉन है। इसका उपयोग खाने में किया जाता है। झींगा पालन करने के लिए खास तौर पर खारे पानी की जरूरत होती है, परंतु लगभग 100 प्रजातियां ऐसी हैं जिनका पालन मीठे पानी में भी किया जा सकता है। भारत में खासतौर पर समुद्र तटीय राज्यों में झींगा पालन किया जाता है, परंतु इसकी डिमांड और आमदनी के कारण इसका पालन पूरे भारत में किया जा रहा है।

झींगा एक पोषक तत्व से भरपूर और कम कैलोरी वाला समुद्री भोजन है। झींगा में कई तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन A, D, E, B1, B2 B3, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और आयोडीन मौजूद होता है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है | झींगा खाने के कुछ और भी तरह के लाभ होते हैं जैसे कि झींगा में पाए जाने वाला एंटी एजिंग हमारे बालों और त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके सेवन से हमारे शरीर के सूजन से लड़ने में सहायता मिलती है। इसके सेवन से कैंसर के खतरे को काम किया जा सकता है और झींगा सेवन से हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है। झींगा में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। झींगा एक कम कैलोरी वाला भोजन है | इसके सेवन से हमारे शरीर का वजन नियंत्रित रहता है और इसके सेवन से हमारे आंखों की रोशनी तेज होती है।

झींगा पालन कैसे करें

झींगा पालन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको तालाब को तैयार कर लेना होगा या फिर अगर आप पहले से ही मछलियों का पालन कर रहे हैं तो उसके साथ भी झींगा पालन कर सकते हैं। शुरुआत में झींगा पालन करने के लिए आप कम जगह का का इस्तेमाल कर सकते हैं। झींगा पालन करने के लिए अपने नजदीकी कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेनी चाहिए तथा भूमि की गुणवत्ता को जांच के उसमें झींगा पालन करना चाहिए।

तालाब की तैयारी

झींगा पालन करने के लिए तालाब को तैयार करना पड़ता है | जिसका आकार पर्याप्त और 7 से 8 फिट गहरा होना चाहिए। झींगा पालन करने के लिए अच्छी खेत और ऐसे स्थान का चयन करें। जहां पर पानी की अच्छी व्यवस्था हो। जिस स्थान पर झींगा पालन करें | वह साफ सुथरी हो और वहां का पानी भी साफ हो। आप जिस भूमि में झींगा पालन करें उस मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 के बीच होना चाहिए इसको नियंत्रित करने के लिए चुने का भी प्रयोग किया जाता है। तालाब के किनारे कुछ कीटनाशकों का प्रयोग करें, जिससे झींगा रोग रहित रहे। तालाब तैयार हो जाने के बाद तालाब में गोबर की खाद को डालें। जिससे उनकी शारीरिक वृद्धि के साथ उनकी प्रजनन क्षमता में भी वृद्धि होती है।

झींगा की प्रमुख प्रजातियाँ

झींगे की लगभग 300 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। झींगा खास तौर पर खारे पानी का जीव है परंतु बहुत सी किस्में ऐसी हैं, जो कि मिठे पानी में भी रहते हैं। कुछ झींगा की प्रजाति पानी के अनुसार वर्गीकृत की गई है।

झींगा पालन में जल उपचार

इनको स्वस्थ रखने के लिए झींगा पालन में उपयोग किए जाने वाले तालाब के पानी को उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है। पानी को उपचारित न करने पर झींगे के स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ सकता है इसके लिए आप अपने नजदीकी विशेषज्ञों की मदद से पता करें कि पानी में कौन-कौन से तत्व मौजूद हैं। अगर पानी में अमोनिया की मात्रा अधिक हो जाए तो पानी में गुड़ को मिश्रित कर दे। इसे पानी के अमोनिया काम हो जाएगी अमोनिया अधिक होने से झींगों के करने का खतरा बना रहता है। झींगा सर्वाहारी होते हैं। झींगा पालन में एक गोली खिलाई जाती है जो की चिकन गोली की तरह दिखाई देती है। साथ ही इनको को मछली का भोजन, मछली का तेल, सोयाबीन तथा कुछ वनस्पतिक प्रोटीन दिए जाते हैं। इससे उनकी वृद्धि अच्छे से होती है।

तालाब में झींगा कैसे डालें

झींगा पालन के लिए नर्सरी की आवश्यकता होती। नर्सरी में आपको झींगे के छोटे-छोटे लार्वे मिलेंगे। जिनको आप पैकेट में तालाब का पानी भरकर 15 मिनट तक रखना होगा। जिससे पैकेट के पानी और तालाब के पानी का तापमान समान हो जाए। इसके बाद सभी जिनको को छोटे-छोटे गड्ढे या फिर किसी ड्रम में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ छोड़ जाता है। जब उनका आकार 3 से 4 ग्राम तक हो जाए तब उन्हें सावधानी से तालाब में छोड़ें। तालाब में छोड़ जाने पर झींगों के बच्चे 50 से 70% ही जिंदा रह पाते हैं। झींगा पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय अप्रैल से जुलाई का महीना होता है झींगा पालन में लगभग 8 से 12 महीने का समय लगता है इसके बाद झींगे लगभग 50 से 100 ग्राम के हो जाते हैं।

पैदावार और मुनाफा

झींगा पालन में अगर अच्छे से देखने की जाए तो एक एकड़ में लगभग 3 टन झींगे प्राप्त होते हैं। झींगा पालन में मुनाफे की बात की जाए तो बाजार में झींगा 350 से 400 रुपए किलो की दर से बिकता है। परन्तु किसानों को कम रेट मिल पाता है। जिनको खरीदने के लिए व्यापारी आते हैं जो की झींगों के हिसाब से किसानों को पैसा देते हैं। झींगा पालन में एक एकड़ की बात की जाए तो इसमें कम से कम10 से 15 लाख की कमाई की जा सकती है।

न्यू देहली पोस्ट

भारत-चीन में बढ़ी बातचीत की सम्भावना पीएम मोदी के बयान से खुश हुआ ड्रैगन

इंटरनेशनल डेस्क

पीएम मोदी ने पिछले दिनों एक पॉडकास्ट पर चीन की चर्चा की और चीन भारत का मुरीद हो गया। चीन अब कहता फिर रहा है कि वैश्विक शांति के लिए दोनों देशों का सहयोग आवश्यक। चीन ने चीन-भारत संबंधों पर प्रधानमंत्री मोदी की 'सकारात्मक' टिप्पणियों की सराहना की है। चीन ने बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन-भारत संबंधों पर 'सकारात्मक' टिप्पणियों की 'सराहना' की, जिसमें उन्होंने मतभेद के बजाय संवाद को तरजीह दी है और कहा कि दोनों पक्षों के लिए आपसी सफलता में योगदान देने वाला हाथी और ड्रैगन के बीच सहयोगात्मक नृत्य ही एकमात्र विकल्प है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों पर एक सवाल का जवाब देते हुए प्रेस के सामने कई बातें कही है। माओ ने कहा कि अक्टूबर में रूस के कज़ान में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सफल बैठक ने द्विपक्षीय संबंधों के सुधार और विकास के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया।दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण साझा समझ पर गंभीरता से अमल किया है, आदान-प्रदान को मजबूत किया है और सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं।

माओ ने कहा, "मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि 2000 से अधिक वर्षों के इतिहास में दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान बनाए रखा है" और दोनों देशों ने सभ्यतागत उपलब्धियों और मानव प्रगति में योगदान देते हुए एक-दूसरे से सीखा है।उन्होंने कहा कि दो सबसे बड़े विकासशील देशों के रूप में, चीन और भारत ने अपने विकास और पुनरोद्धार को गति देने के कार्य को साझा किया है और एक-दूसरे की सफलताओं को समझा और उनका समर्थन किया है।उन्होंने कहा कि यह 2.8 बिलियन से अधिक लोगों के मौलिक हितों की पूर्ति करता है, क्षेत्रीय देशों की आम आकांक्षाओं को पूरा करता है और वैश्विक दक्षिण के मजबूत होने और विश्व शांति के लिए अनुकूल होने की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का अनुसरण करता है।

उन्होंने कहा कि चीन दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण आम समझ को लागू करने, राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ को एक अवसर के रूप में लेने और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और सुदृढ़ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। अपने पॉडकास्ट में, मोदी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच 2020 की झड़पों से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए राष्ट्रपति शी के साथ उनकी हालिया बातचीत के बाद भारत-चीन सीमा पर सामान्य स्थिति लौट आई है।

बता दें कि पिछले दिनों अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट में, पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन सीमा पर 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़पों से पहले वाली स्थितियों को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक का जिक्र करते हुए कहा, "राष्ट्रपति शी के साथ हाल में हुई बैठक के बाद हमने सीमा पर सामान्य स्थिति की वापसी देखी है. हम अब 2020 से पहले की स्थितियों को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से, विश्वास, उत्साह और ऊर्जा वापस आनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से, इसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि विवाद में पांच साल चले गए हैं।''

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग न केवल दोनों देशों के लिए लाभकारी है, बल्कि वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, ''चूंकि 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम चाहते हैं कि भारत और चीन स्वस्थ और स्वाभाविक तरीके से प्रतिस्पर्धा करें। प्रतिस्पर्धा बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसे कभी संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए।'' पीएम मोदी ने यह बी ही कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध नए नहीं हैं। दोनों देशों की संस्कृति और सभ्यताएं प्राचीन हैं। उन्होंने कहा, ''आधुनिक दुनिया में भी, वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप ऐतिहासिक रिकॉर्ड को देखें तो सदियों से भारत और चीन ने एक-दूसरे से सीखा है। साथ मिलकर, उन्होंने हमेशा किसी न किसी तरह से वैश्विक भलाई में योगदान दिया है। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि एक समय भारत और चीन अकेले दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखते थे। भारत का कितना बड़ा योगदान था। मेरा मानना है कि गहरे सांस्कृतिक संबंधों के साथ हमारे संबंध बेहद मजबूत रहे हैं।''

तीन घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम सदियों पीछे मुड़कर देखें तो भारत और चीन के बीच संघर्ष का कोई वास्तविक इतिहास नहीं है। उन्होंने कहा, ''यह हमेशा एक-दूसरे से सीखने और एक-दूसरे को समझने के बारे में रहा है। एक समय चीन में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था और उस दर्शन का उद्भव भारत में हुआ। भविष्य में भी हमारे संबंध उतने ही मजबूत रहने चाहिए और आगे बढ़ते रहने चाहिए। मतभेद स्वाभाविक हैं. जब दो पड़ोसी देश होते हैं, तो कभी-कभी असहमति होती है। '' प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवार में भी सब कुछ सही नहीं होता, लेकिन हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि मतभेद, विवाद में तब्दील नहीं हो। उन्होंने कहा, ''इसलिए हम सक्रिय रूप से बातचीत की दिशा में काम कर रहे हैं। विवाद के बजाय, हम बातचीत पर जोर देते हैं, क्योंकि केवल बातचीत के माध्यम से हम एक स्थायी सहकारी संबंध का निर्माण कर सकते हैं।

इजरायली हमले में गाजा पट्टी लहूलुहान

इंटरनेशनल डेस्क

इजरायल के हमले से गाजा पट्टी लहूलुहान हो गया। इजरायल का यह हमला तब हुआ जब दुनिया भर में शांति वार्ता की बात की जा रही है और दुनिया के कई देश सीजफायर चाहते हैं। लेकिन इजरायल जिस अंदाज में अचानक हमला किया है उससे फिलिस्तीन की कमर ही टूट गई है। जाहिर है हमास भी अब चुकने को तैयार नहीं होगा और बदले की भावना के साथ वह भी कोई बड़ा हमला कर सकता है। आगे क्या होगा यह देखने की बात हो सकती है लेकिन हमास और इजरायल के बीच जारी खुनी संघर्ष मानव समाज के लिए बेहद खतरनाक साबित होता जा रहा है। इजराइल ने पिछले दिनों गाजा पट्टी क्षेत्र में भीषण हवाई हमले किए, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 404 फलस्तीनी मारे गए। और यह जानकारी अस्पताल के अधिकारियों ने दी है। अचानक किए गए इस हमले की वजह से जनवरी से लागू संघर्ष विराम टूट गया और अब 17 महीने से जारी युद्ध के फिर से शुरू होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

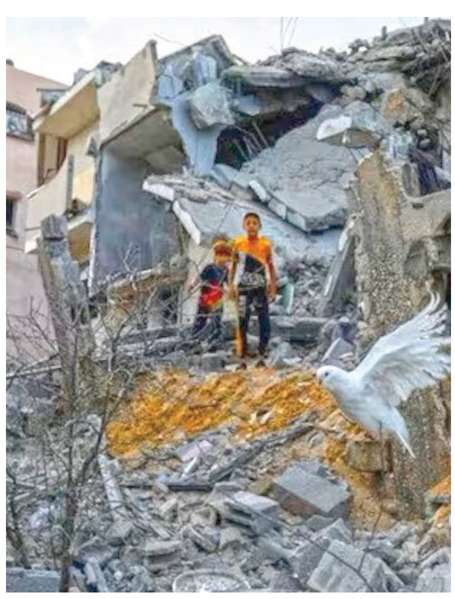

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम समझौते में बदलाव की इजराइली मांग को हमास द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद हमले का आदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि हमले का दायरा बढ़ने की संभावना है। उधर ,अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय एवं आवास 'व्हाइट हाउस' ने कहा कि हमला करने से पहले उससे सलाह ली गई है और उसने इजराइल के फैसले का समर्थन किया। इजरायली सेना ने लोगों को पूर्वी गाजा छोड़ने और मध्य की ओर बढ़ने का आदेश दिया, जिससे संकेत मिलते हैं कि इजराइल जल्द ही नये सिरे से जमीनी स्तर पर सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा, ''इजराइल अब सैन्य ताकत बढ़ाकर हमास के खिलाफ कार्रवाई करेगा।''

रमजान के महीने के दौरान हुए इस हमले से वह युद्ध फिर से शुरू हो सकता है, जिसमें पहले ही हजारों फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और गाजा में व्यापक तबाही हुई है। साथ ही, इससे हमास द्वारा बंधक बनाए गए लगभग दो दर्जन इजराइली बंधकों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे अभी भी जीवित हैं। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नेतन्याहू का युद्ध फिर से शुरू करने का फैसला शेष बंधकों के लिए "मौत की सजा" के बराबर है।इज्जत अल-रिशेक ने नेतन्याहू पर अपने गठबंधन को बचाने के लिए हमले शुरू करने का आरोप लगाया और मध्यस्थों से कहा कि वे इस तथ्य का खुलासा करें कि संघर्षविराम किसने तोड़ा। हमास ने कहा कि मंगलवार के हमलों में कम से कम चार वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब नेतन्याहू पर इजराइल में दबाव बढ़ रहा है, बंधक संकट से निपटने के उनके तरीके और इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख को बर्खास्त करने के उनके फैसले को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। हमलों के बाद, लंबे समय से जारी भ्रष्टाचार के मुकदमे में उनकी हालिया गवाही रद्द कर दी गई।

बंधकों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य समूह ने सरकार पर संघर्षविराम से पीछे हटने का आरोप लगाया और कहा कि उसने ''बंधकों के मुद्दे को छोड़ने का विकल्प चुना।''बंधकों और लापता परिवारों के संगठन ने एक बयान में कहा, "हम अपने प्रियजनों को हमास की भयानक कैद से वापस लाने की प्रक्रिया को जानबूझकर खत्म करने से हैरान, क्रोधित और भयभीत हैं।' जानकारी के मुताबिक मृतक के शव यूरोपियन अस्पताल में लाये गए। यूरोपियन अस्पताल के अनुसार, दक्षिणी शहर राफा में एक मकान पर हुए हमले में एक परिवार के 17 सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें कम से कम 12 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।मृतकों में पांच बच्चे, उनके माता-पिता और एक अन्य व्यक्ति और उसके तीन बच्चे शामिल हैं। दक्षिणी शहर खान यूनिस में, 'एसोसिएटेड प्रेस' के संवाददाताओं ने विस्फोट की आवाज सुनी और धुएं के गुबार देखे। घायल लोगों को एंबुलेंस से नासर अस्पताल लाया गया, जहां मरीज फर्श पर पड़े थे, कुछ दर्द से कराह रहे थे। कई फिलिस्तीनियों ने कहा कि उन्हें युद्ध के फिर से शुरू होने की आशंका थी, जब संघर्षविराम के दूसरे चरण पर बातचीत फरवरी की शुरुआत में तय समय पर शुरू नहीं हो सकी। इसके बजाय, इजराइल ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव अपनाया और हमास पर इसे स्वीकार करना का दबाव बनाने के लिए क्षेत्र के 20 लाख फिलिस्तीनियों को भोजन, ईंधन और अन्य सहायता के सभी आपूर्ति रोक दी।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमलों में कम से कम 404 लोग मारे गए और 560 से अधिक घायल हुए। बचावकर्मी अभी भी मलबे में मृतकों और घायलों की तलाश कर रहे हैं, जबकि हमले जारी हैं। उधर ,व्हाइट हाउस ने नये सिरे से युद्ध छिड़ने के लिए हमास को दोषी ठहराया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूजेस ने कहा कि आतंकवादी समूह "संघर्ष विराम को विस्तारित करने के लिए बंधकों को रिहा कर सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने इनकार करने और युद्ध का विकल्प चुना।'' एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि इजरायल हमास की सेना, नेताओं और बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है और हवाई हमलों से परे सैन्य अभियान का विस्तार करने की योजना बना रहा है। बता दें कि संघर्ष विराम के दूसरे चरण पर बातचीत रुक गई थी। युद्ध को रोकने के लिए संघर्ष विराम होने के दो महीने बाद हमले किए गए। छह सप्ताह से अधिक समय में, हमास ने संघर्ष विराम के पहले चरण में लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 25 इजराइली बंधकों को रिहा किया और आठ अन्य के शव सौंपे।हालांकि, दो सप्ताह पहले संघर्षविराम समाप्त होने के बाद से, दोनों पक्ष दूसरे चरण के लिए आगे बढ़ने के तरीके पर सहमत नहीं हो पाए, जिसका उद्देश्य शेष 59 बंधकों को रिहाई कराना है।

हमास ने शेष बंधकों की रिहाई के बदले में युद्ध को समाप्त करने और इजरायली सैनिकों की पूरी तरह से वापसी की मांग की है। वहीं, इजराइल का कहना है कि जब तक वह हमास की शासन और सैन्य क्षमताओं को नष्ट नहीं कर देता और सभी बंधकों को मुक्त नहीं करा लेता, वह युद्ध समाप्त नहीं करेगा। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि हमास ने "हमारे बंधकों को रिहा करने से बार-बार इनकार किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ और मध्यस्थों से प्राप्त सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है।'' इजराइल चाहता है कि हमास स्थायी संघर्ष विराम के लिए बातचीत करने के वादे के बदले में शेष बंधकों में से आधे को रिहा करे। वहीं, हमास दोनों पक्षों द्वारा किए गए संघर्ष विराम समझौते का पालन चाहता है, जिसमें संघर्षविराम के अधिक कठिन एवं दूसरे चरण पर बातचीत शुरू करने की बात कही गई है। इसमें शेष बंधकों को रिहा किया जाएगा और इजराइली सेना गाजा से वापस चली जाएगी।

अनोखी है अमीर खान की तीसरी लव स्टोरी

फिल्मी डेस्क

60 साल के हो चुके अभिनेता अमीर खान ने एक बड़ा खुलासा कर सबको चौंका दिया है। वे फिर से शादी करने के मूड में हैं और उन्होंने अपनी गर्ल फ्रेंड से भी सबको मिला दिया है। 13 मार्च को अपने प्री-बर्थडे मीट एंड ग्रीट में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से मीडिया को मिलवा कर सबको सकते में डाल दिया।

अमीर खान की नयी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट ने भी खुलासा किया है कि आखिर वो आमिर खान की किस बात पर फिदा हो गई थीं। गौरी स्प्रैट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आमिर उन्हें क्यों भा गए। उन्होंने कहा-"मैं ऐसा व्यक्ति चाहती थी जो दयालु, संवेदनशील और परवाह करने वाला हो।" इस पर आमिर ने मजाकिया अंदाज में कहा-"और इन सबके बाद, तुम्हें मैं मिल गया?"

आमिर और गौरी के रिश्ते की बात की जाए तो उनकी पहली मुलाकात 25 साल पहले हुई थी, लेकिन दोनों काफी समय तक संपर्क में नहीं थे। दो साल पहले फिर से मुलाकात हुई और दोनों रिश्ते में आ गए। आमिर ने अपने नए रिलेशनशिप पर बात करते हुए कहा-"मैं ऐसे इंसान की तलाश में था जो मुझे शांति दे, और वो गौरी थी।"

गौरी का फिल्म इंडस्ट्री से कोई खास जुड़ाव नहीं है। उन्होंने आमिर की ज्यादातर फिल्में नहीं देखी हैं। सिर्फ 'दिल चाहता है' और 'लगान' देखी है। आमिर ने कहा-"वो मुझे सुपरस्टार के तौर पर नहीं, बल्कि एक पार्टनर के रूप में देखती हैं।"

तीसरी शादी के सवाल पर आमिर ने कहा-"60 साल की उम्र में शादी शोभा देती है या नहीं, ये मैं नहीं जानता।" उन्होंने बताया कि उनके बच्चे गौरी को पसंद करते हैं और वह अपनी दोनों पूर्व पत्नियों से भी अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं। गौरी 6 साल के बेटे की माँ है।

'कुली' से श्रुति हासन का नया पोस्टर आउट

खेल डेस्क

आगामी फिल्म 'कुली' के निर्माताओं ने श्रुति हासन का नया लुक जारी कर दिया है। प्रीति के रूप में श्रुति हासन का नया लुक गंभीर लेकिन प्रभावशाली अंदाज में सामने आया है। उनका किरदार गंभीर नजर आ रहा है।निर्माताओं ने पहले एक आकर्षक पोस्टर के साथ श्रुति के किरदार को पेश किया था। फिल्म में रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं। 'कुली' के अलावा, श्रुति की हालिया रिलीज फिल्म 'द आई' ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में दिल जीत रही है। हाल ही में इस फिल्म का भारतीय प्रीमियर वेंच फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसे काफी प्रशंसा मिली।

इससे पहले अभिनेत्री ने शेयर किया था कि वह ऐसी कहानियों की ओर आकर्षित होती हैं, जिसमें प्यार, खुद की खोज शामिल होती है। अभिनेत्री ने यह भी कहा कि 'द आई' ने उन्हें स्क्रीन पर इन सभी भावनाओं का सामना करने का मौका दिया। यह फिल्म ग्रीस के बैकग्राउंड पर आधारित है। श्रुति हासन ने बताया था, "मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे पता चला कि यह फिल्म तो मेरे लिए ही बनी है। मैं हमेशा ऐसी कहानियों की ओर आकर्षित होती रही हूं, जिसमें प्यार, आत्म-खोज का पुट हो और जो मेरे साथ गहराई से जुड़ती हैं।" उन्होंने कहा, " 'द आई' में प्रतिभाशाली महिला क्रिएटिव टीम के साथ काम करके मुझे शानदार अनुभव मिला।"

ग्रीस के लुभावने परिदृश्यों पर आधारित, 'द आई' में श्रुति ने डायना का रोल निभाया है। कहानी में डायना की भावनात्मक यात्रा दिखाई गई है जिसमें उनके पति का देहांत हो चुका है।फिल्म का निर्देशन डेफ्ने शिमोन ने किया है और इसका निर्माण फिंगरप्रिंट कंटेंट ने किया है। इसकी पटकथा अवार्ड विनिंग लेखका एमिली कार्लटन ने लिखी है।

लम्बी दूरी की धाविका अर्चना जाधव हुई प्रतिबंधित

खेल डेस्क

भारत की लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव पर जनवरी में डोप परीक्षण में विफल रहने के कारण पिछले मंगलवार को चार साल का प्रतिबंध लगा दिया गया।अर्चना ने बार-बार याद दिलाने पर भी डोप परीक्षण में असफल रहने के खिलाफ अपील नहीं की जिससे विश्व एथलेटिक्स ने यह मान लिया कि वह अपना अपराध स्वीकार करती है और इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया। विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट के अनुसार, जाधव का जो नमूना पिछले साल दिसंबर में पुणे हाफ-मैराथन के दौरान लिया गया था, उसमें प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सेंड्रोलोन था। यह सिंथेटिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड शरीर में प्रोटीन उत्पादन और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। प्रतिबंध सात जनवरी से लागू हुआ। जाधव इस अवधि के लिए अस्थायी तौर पर निलंबित थी। 15 दिसंबर 2024 से उनके सभी परिणाम अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें इस अवधि के लिए सभी पुरस्कार, पदक, अंक, पुरस्कार और उपस्थिति राशि जमा करने होंगे। उन्होंने 25 फरवरी को एआईयू को एक ईमेल में उल्लंघन के आरोप का जवाब देते हुए कहा था, ''मुझे बेहद खेद है सर...मैं आपके फैसले का स्वागत करती हूं।''एआईयू ने कहा कि इस संवाद को लेकर उसकी समझ यह थी कि जाधव को सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी और वह निकाय से निर्णय से संतुष्ट थी।

एआईयू ने कहा कि फिर भी जाधव को सूचित किया गया कि उनके पास यह स्वीकार करने के लिए तीन मार्च तक का समय है कि उन्होंने डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया है। इसके बाद भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने 28 फरवरी को उन्हें इसकी याद दिलाई। हालांकि, एआईयू को जाधव से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने आखिरी बार अक्टूबर 2024 में दिल्ली हाफ मैराथन में भाग लिया था, जिसमें भारतीय महिला खिलाड़ियों में लिली दास, कविता यादव और प्रीति लांबा के पीछे चौथे स्थान पर रहीं थी।जाधव का 10,000 मीटर में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 35:44.26 और हाफ मैराथन में 1:20:21 है। 3,000 मीटर में उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10:28.82 है।

पहली महिला फॉर्मूला 4 रेसर बनी श्रिया लोहिया

खेल डेस्क

हिमाचल प्रदेश की श्रिया लोहिया भारत की पहली महिला रेसर बन गई है। श्रिया लोहिया महज 9 साल की उम्र से रेसिंग की दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुकी थीं। श्रिया लोहिया ने मोटरस्पोर्ट्स के इतिहास में अपनी एक खास पहचान बनाई है। वह फॉर्मूला 4 रेसिंग में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर बनीं। केवल 16 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय फॉर्मूला 4 चैम्पियनशिप के उद्घाटन सेशन में हैदराबाद ब्लैकबर्ड्स टीम से प्वाइंट्स स्कोर किए. जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह टीम भारत की प्रमुख रेसिंग टीमों में से एक है।

श्रिया की मोटरस्पोर्ट्स में करियर की शुरुआत महज 9 साल की उम्र से हुई थी जब उन्होंने कर्टिंग में पार्टिसिपेट किया था। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के कारण उन्होंने जल्दी ही अपनी पहचान बनाई और कई प्रतियोगिताओं में 30 से अधिक पोडियम फिनिश हासिल किए। उनकी निरंतर सफलता और समर्पण ने उन्हें फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया से चार सम्मान मिल चुके हैं।

2022 में श्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो बच्चों को मिलने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार मोटरस्पोर्ट्स में उनकी एक्सीलेंस को मान्यता देता है। श्रिया की उपलब्धियां भारत में महिला रेसर्स के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं। यह साबित करते हुए कि इस पुरुष प्रधान खेल में भी प्रतिभा और संकल्प से सफलता पाई जा सकती है। श्रिया लोहिया का जन्म हिमाचल प्रदेश के सुंदर नगर में हुआ था। वह न केवल मोटरस्पोर्ट्स में सफल हो रही हैं बल्कि अपनी पढ़ाई में भी होमस्कूलिंग के माध्यम से संतुलन बनाए हुए हैं। वर्तमान में वह कक्षा 11 की विज्ञान की छात्रा हैं और दोनों क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। उनका सपना है कि वह भारत की कुछ चुनिंदा फॉर्मूला वन ड्राइवरों में से एक बनें और इसके जरिए अन्य युवाओं को मोटरस्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए प्रेरित करें।

रेसिंग के अलावा श्रिया एक बहु-प्रतिभाशाली एथलीट भी हैं और उन्हें बास्केटबॉल, बैडमिंटन, पिस्टल शूटिंग, साइक्लिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में खास इंट्रेस्ट है। ये खेल उनके फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देते हैं। ये सब एक पेशेवर रेसिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रिया का मोटरस्पोर्ट्स के प्रति जुनून केवल अपने करियर तक सीमित नहीं है वह कई रेसिंग फॉर्मेट्स जैसे फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, फॉर्मूला ई और वर्ल्ड रैली चैम्पियनशिप को भी फॉलो करती हैं। उनकी रेसिंग जर्नी की शुरुआत रोटैक्स मैक्स इंडिया कर्टिंग चैम्पियनशिप में हुई थी।

पत्रकारिता को नए सिरे से परिभाषित करते हुए न्यू देहली पोस्ट की शानदार प्रस्तुति अब आपके सामने है। इसमें होंगी खोजी और जानबूझ कर दबाई गई ख़बरों के उद्भेदन की शानदार प्रस्तुति - न्यू दिल्ली पोस्ट प्रिंट और डिजिटल के सभी मंचो के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है :-

NEW DELHI POST

न्यू देहली पोस्ट
(साप्ताहिक हिंदी)

हमारे ये सभी डिजिटल मंच सभी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। यहाँ जाकर आप ताजातरीन ख़बरों और विश्लेषण को देख समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं।

Website: https://newdelhipost.co.in/
: @NewDelhiPost
: https://www.facebook.com/NewDelhiPosts
: @NewDelhiPost
:newdelhipost_official

न्यू देहली पोस्ट
B-614, 6th Floor Tower B
Noida One Building
Noida Sector 62, Gautam Budh Nagar (UP)
Pin Code -201309

संपर्क करे - Email - postnewdelhi@gmail.com